



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 14—अप्रैल 20, 2018 (चैत्र 24, 1940)

No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 14—APRIL 20, 2018 (CHAITRA 24, 1940)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

कार्पोरेशन बैंक

(सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक)

(प्रधान कार्यालय, मंगलूर)

मंगलूर, 17 फरवरी, 2018

सं. का.प्र.प.आ० सं:2469:2017-18.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 19 और 12 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्पोरेशन बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से कार्पोरेशन बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1982 में आगे संशोधन हेतु एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

- (1) इन विनियमों को कार्पोरेशन बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2017 कहा जाएगा।
(2) इन विनियमों में जहाँ कहीं भी वर्णन दिया गया है उसको छोड़कर, ये विनियम 1 नवंबर, 2007 से प्रभावी माने जाएंगे।
- कार्पोरेशन बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1982 (इसके बाद उक्त विनियम के रूप में संदर्भित होगा) के विनियम 3 में—
(i) खंड (च), के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित होंगे, अर्थात् :-

(च) “परिवार” का अर्थ अधिकारी की पत्नी/पति, पूर्णतया आश्रित अविवाहित बच्चे (जिसमें आश्रित सौतेला तथा कानूनन गोद लिए गए बच्चे शामिल हैं), चालीस प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता के साथ शारीरिक रूप से विकलांग भाई या बहन और माता-पिता जो सामान्यतया अधिकारी के साथ रहते हैं और उन पर पूर्णतया आश्रित हैं।

स्पष्टीकरण:- इस खण्ड का प्रयोजन अधिकारी पर पूर्णतया आश्रित बच्चे या माता-पिता या शारीरिक रूप से विकलांग भाई या बहन का अर्थ उन बच्चों या माता-पिता, भाई या बहन से है जिनकी आय प्रतिमाह ₹3,500/- से अधिक नहीं है। किंतु, यदि माता-पिता में से किसी एक की आय ₹3,500/- प्रतिमाह से अधिक है या माता-पिता दोनों की समग्र आय ₹3,500/- प्रतिमाह से अधिक है, तो माता-पिता दोनों को अधिकारी पर पूर्णतया आश्रित नहीं माना जाएगा।

(ii) खंड (ओ) को हटा दिया जाएगा

3. उक्त विनियमों के विनियम 4 में,

(i) उप विनियम (4ए) को हटा दिया जाएगा;

(ii) उप विनियम (4ए) को हटाने के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़े जाएंगे, अर्थात् –

(5) नीचे दिए गए प्रत्येक श्रेणी के सामने विनिर्दिष्ट वेतनमान 01 नवंबर, 2007 से लागू होंगे:

(क) उच्च कार्यपालक श्रेणी

वेतनमान VII = ₹ 46800 – 1300/4 – 52000

वेतनमान VI = ₹ 42000 – 1200/4 – 46800

(ख) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान V = ₹ 36200 – 1000/2 – 38200 – 1100/2 – 40400

वेतनमान IV = ₹ 30600 – 900/4 – 34200 – 1000/2 – 36200

(ग) मध्य प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान III = ₹ 25700 – 800/5 – 29700 – 900/2 – 31500

वेतनमान II = ₹ 19400 – 700/1 – 20100 – 800/10 – 28100

(घ) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान I = ₹ 14500 – 600/7 – 18700 – 700/2 – 20100 – 800/7 – 25700

स्पष्टीकरण- 31 अक्टूबर, 2007 को लागू वेतनमानों द्वारा शासित होने वाले प्रत्येक अधिकारी का नियमन 01 नवंबर, 2007 को इस उप विनियम में निर्धारित वेतनमान में प्रक्रम-दर-प्रक्रम आधार पर किया जाएगा, अर्थात् पहले प्रक्रम से तदनुरूपी प्रक्रमों पर और वेतनवृद्धियाँ, अन्यथा उप बंधित को छोड़कर, सामान्यतया अधिवर्षिता तारीख को होंगी।

(6) उप-विनियम (1), (2), (3), (4) और (5) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि बैंक के लिए हर समय इन सभी श्रेणियों में अधिकारी रखना अपेक्षित है।

4. उक्त विनियमों के विनियम 5 में,

(क) उप-विनियम (1) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित होंगे, अर्थात् –

(1) विनियम 4 के उप-विनियम (5) के उपबंधों के अधीन, 01 नवंबर 2007 को और उस तारीख से, वेतनवृद्धियाँ निम्नानुसार मंजूर की जाएंगी, अर्थात् –

(क) विनियम 4 के उप-विनियम (5) में उपर्युक्त वेतनमानों में विनिर्दिष्ट वेतनवृद्धियाँ, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अध्यधीन वार्षिक आधार पर प्रोद्भूत होंगी और वे जिस महीने में देय होती हैं उस महीने की पहली तारीख को दी जाएंगी;

(ख) जो अधिकारी कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान I में उच्च स्तर तक पहुँचने के बाद मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II के लिए वेतनमान की श्रेणी के लिए चले गए हैं वे प्रत्येक तीन पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए चार गतिरोध वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे, जिनमें से पहले दो प्रत्येक ₹800/- और अगले दो प्रत्येक ₹900/- होंगे :

परंतु, जो अधिकारी 01 नवंबर, 2007 को दूसरी गतिरोध वेतनवृद्धि की प्राप्ति के बाद तीन साल या उससे अधिक का समय पूर्ण कर लेते हैं, उन्हें 01 नवंबर, 2007 को तीसरी गतिरोध वेतनवृद्धि दी जाएगी और अन्य कोई गतिरोध वेतनवृद्धि 01 नवंबर, 2008 को या उसके बाद दूसरी गतिरोध वेतनवृद्धि की प्राप्ति के पश्चात उनके छः वर्ष पूर्ण होने पर प्रदान की जाएगी;

(ग) जो अधिकारी मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान ॥ में उच्च स्तर तक पहुंचने के बाद मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान ॥॥ के लिए वेतनमान की श्रेणी के लिए चले गए हैं वे प्रत्येक तीन पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए ₹ 900 की तीन गतिरोध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे :

परंतु, जो अधिकारी 01 नवंबर, 2007 को पहली गतिरोध वेतनवृद्धि की प्राप्ति के बाद तीन साल या उससे अधिक का समय पूर्ण कर लेते हैं, उन्हें अगली गतिरोध वेतनवृद्धि 01 नवंबर, 2007 से प्रभावी होने के साथ दी जाएगी और 01 नवंबर, 2008 को या इसके बाद आगामी गतिरोध वेतनवृद्धि पहली गतिरोध वेतनवृद्धि की प्राप्ति के बाद उनके छः वर्ष पूर्ण होने पर प्रदान की जाएगी :

परंतु यह भी कि मूल मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान ॥॥ में नियुक्त या पदोन्नत अधिकारी प्रत्येक तीन पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए ₹900 की चार गतिरोध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे :

परंतु, जो अधिकारी 01 नवंबर, 2007 को दूसरी गतिरोध वेतनवृद्धि की प्राप्ति के बाद पहले से ही दूसरी गतिरोध वेतनवृद्धि की प्राप्ति तथा सेवा के तीन साल या उससे अधिक का समय पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें तीसरी गतिरोध वेतनवृद्धि 01 नवंबर, 2007 को प्रदान की जाएगी और 01 नवंबर, 2008 को या इसके बाद चौथी गतिरोध वेतनवृद्धि दूसरी गतिरोध वेतनवृद्धि की प्राप्ति के बाद उनके छः वर्ष पूर्ण होने पर प्रदान की जाएगी।

स्पष्टीकरण- इस उप-विनियम के तहत अगले उच्चतर वेतनमान में की गई ऐसी वेतनवृद्धियों को पदोन्नति नहीं माना जाएगा और अधिकारियों के विशेषाधिकार, परिलक्षित्यां, कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व उनके मूल पदों के रूप में जारी रहेंगी।

(ख) उप-विनियम (2) में, -

(i) स्पष्टीकरण में, खंड (ङ) के बाद और टिप्पणी से पहले, निम्नलिखित खंड को जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

“(च) 01 नवंबर 2007 को तथा उसके बाद से, अन्य बातों के समान होने पर, व्यावसायिक अर्हता वेतन की मात्रा निम्नानुसार संशोधित होंगी :-

तालिका

जिन्होंने जेएआईआईबी अथवा सीएआईआईबी उत्तीर्ण कर लिया है।	(i) अधिकतम स्केल तक पहुंचने के एक साल बाद प्रति माह ₹410/-
जिन्होंने सीएआईआईबी के दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिए हैं।	(i) अधिकतम स्केल पर पहुंचने के एक साल बाद प्रति माह ₹410/-
	(ii) अधिकतम स्केल पर पहुंचने के दो साल बाद प्रति माह ₹1030/-

परंतु, यदि किसी अधिकारी ने वेतन के अधिकतम स्केल तक पहुंचने के बाद, जेएआईआईबी अथवा सीएआईआईबी (या तो कोई एक या दोनों भाग) योग्यता प्राप्त कर ली है तो उसे इस तरह की योग्यता प्राप्त करने की तारीख से व्यावसायिक अर्हता वेतन की पहली किश्त दी जाएगी और व्यावसायिक अर्हता वेतन के बाद जारी किश्त व्यावसायिक अर्हता वेतन की पहली किश्त के जारी होने की तारीख के संदर्भ में होगी।

परंतु यह भी कि ऐसे मामलों में जहाँ किसी अधिकारी ने उपरोक्त योग्यता में से कोई एक पहले ही प्राप्त कर ली है और इस तरह की योग्यता प्राप्त करने के कारण कोई वेतनवृद्धि या व्यावसायिक अर्हता वेतन नहीं लिया है, तो उसे 01 नवंबर 2007 से प्रभावी या ऐसी योग्यता प्राप्त करने की तारीख जो भी बाद में है, से व्यावसायिक अर्हता वेतन प्रदान किया जा सकता है।”

(ii) टिप्पणी में, खंड (v) के लिए, निम्नलिखित खंडों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(v) यदि किसी अधिकारी ने, 27 अप्रैल 2010 को उक्त योग्यता में से कोई एक, जैसा कि खंड (iv) में विनिर्दिष्ट है, पहले ही प्राप्त कर ली है और इस तरह की योग्यता प्राप्त करने के कारण कोई वेतनवृद्धि या व्यावसायिक अर्हता वेतन नहीं लिया है, तो उसे 01 नवंबर 2007 से प्रभावी या ऐसी योग्यता प्राप्त करने की तारीख जो भी बाद में है, से व्यावसायिक अर्हता वेतन प्रदान किया जा सकता है।”

(ग) उप-विनियम (3) में, -

(i) खंड (घ) के बाद और टिप्पणी से पहले, निम्नलिखित खंड को जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

“(ङ) 01 नवंबर 2007 को तथा उसके बाद से, अन्य बातों के समान होने पर, आवास किराया भत्ते के साथ-साथ नियत वैयक्तिक वेतन निम्न दरों पर होंगे और सेवा की संपूर्ण अवधि के लिए अवरुद्ध रहेंगे :-

तालिका

वेतनवृद्धि घटक (₹)	वेतन वृद्धि घटकों पर 01.11.2007 को महंगाई भत्ते (₹)	कुल नियत वैयक्तिक वेतन देय जहाँ बैंक का आवास प्रदान किया गया है (₹)
(क)	(ख)	(ग)
800	58	858
900	65	965
1000	72	1072
1100	79	1179
1200	86	1286
1300	94	1394”

(ii) टिप्पणी में, खंड (i) और (ii) के लिए, निम्नलिखित खंडों को दर्ज किया जाएगा, अर्थात् :-

“(i) नियत वैयक्तिक भत्ते अथवा नियत वैयक्तिक वेतन जैसा कि खंड (ख), (ग), (घ) या (ङ) के तहत तालिका के स्तंभ (ग) के रूप में निर्दिष्ट है, उन अधिकारियों को देय होगा जिन्हें बैंक के साथ आवास उपलब्ध कराए जाते हैं।

(iii) आवास किराए भत्ते के लिए पात्र अधिकारियों के लिए नियत वैयक्तिक भत्ते अथवा नियत वैयक्तिक वेतन खंड (ङ) के तहत तालिका के स्तंभ (क) और (ख) के तहत निर्दिष्ट कुल राशि होगी और संबंधित अधिकारी कर्मचारियों द्वारा लिए गए आवास किराए भत्ते जहाँ विनियम 4 के उप-विनियमों (2), (3), (4) या (5) में विनिर्दिष्ट वेतन के संबंधित स्केल की अंतिम वृद्धि अर्जित की जाती है।”

(iii) टिप्पणी के बाद आने वाले खंड (ङ) को उप-खंड (v) के रूप में नामित किया जाएगा और खंड (v) के लिए जैसा कि अंकित किया गया है, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(v) जिस अधिकारी को उपर्युक्त खंड (क) के अनुसार अग्रिम वेतनवृद्धि मिल चुकी है उसे ऊपर खंड (ख), (ग), (घ) या (ङ) में उल्लिखित नियत वैयक्तिक भत्ते/नियत वैयक्तिक वेतन की प्रमात्रा, वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात प्राप्त होगी।”

5. उक्त विनियमों के विनियम 21 में,

- (i) उप-विनियम (3) में, टिप्पणी को हटा दिया जाएगा;
- (ii) उप-विनियम (4) में, टिप्पणी को हटा दिया जाएगा;
- (iii) उप-विनियम (4) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियमों और टिप्पणियों को जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

“(5) 01 नवंबर 2007 को या उसके बाद से, अखिल भारतीय औसत कामगार वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार पर 1960=100 के तिमाही औसत में 2838 अंकों से अधिक प्रति 4 अंकों के उतार या चढ़ाव के लिए महंगाई भत्ता वेतन का 0.15% देय होगा।”

स्पष्टीकरण- इस उप-विनियम के प्रयोजनों के लिए,

- (क) महंगाई भत्ते के प्रयोजन हेतु “वेतन” का अर्थ अवरोध वेतनवृद्धि सहित मूल वेतन होगा।
- (ख) विनियम 5 के उप-विनियम (2) के स्पष्टीकरण (ग), (घ), (ङ) और (च) में निर्दिष्टानुसार, व्यावसायिक अर्हता भत्ते या व्यावसायिक अर्हता वेतन को महंगाई भत्ते के लिए गिना जाएगा।

6. उक्त विनियमों के विनियम 22 में, उप-विनियम (1) और (2) के लिए निम्नलिखित उप-विनियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(1) 01 नवंबर 2002 को या उसके बाद से,

- (क) यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है तो उससे वह जिस वेतनमान में है उसके प्रथम प्रक्रम में मूल वेतन के 1.75% के बराबर रकम या आवास हेतु मानक किराया, जो भी कम हो, वसूल किया जाएगा;
- (ख) यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान नहीं की जाती है तो वह निम्नलिखित दरों पर मकान किराया भत्ता पाने का पात्र होगा, अर्थात् :

तालिका

जहाँ कार्यस्थल है	मकान किराया भत्ता देय होगा
(1)	(2)
(i) वर्ग ए में प्रमुख “ए” श्रेणी के शहरों और परियोजना क्षेत्र केन्द्रों में	वेतन का 8.5%
(ii) वर्ग बी में क्षेत्र । और परियोजना क्षेत्र केन्द्रों में अन्य स्थानों में	वेतन का 7.5%
(iii) अन्य स्थानों में	वेतन का 6.5%

परंतु यदि कोई अधिकारी किराए की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भत्ता, जिस वेतनमान में वह है उसके प्रथम प्रक्रम के 1.75% से अधिक, उसके द्वारा अपने आवास के लिए दिया गया वास्तविक किराया ऊपर स्तंभ (2) के अनुसार देय मकान किराया भत्ते का अधिकतम 150% देय होगा ।

(2) 01 नवंबर 2007 को या उसके बाद से,

- (क) यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है तो उससे वह जिस वेतनमान में है उसके प्रथम प्रक्रम में मूल वेतन के 1.20% के बराबर रकम या आवास हेतु मानक किराया, जो भी कम हो, वसूल किया जाएगा;
- (ख) यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान नहीं की जाती है तो वह निम्नलिखित दरों पर मकान किराया भत्ता पाने का पात्र होगा, अर्थात्:-

तालिका

जहाँ कार्यस्थल है	मकान किराया भत्ता देय होगा
(1)	(2)
(i) वर्ग ए में प्रमुख “ए” श्रेणी के शहरों और परियोजना क्षेत्र केन्द्रों में	वेतन का 8.5%
(ii) वर्ग बी में क्षेत्र । और परियोजना क्षेत्र केन्द्रों में अन्य स्थानों में	वेतन का 7.5%
(iii) अन्य स्थानों में	वेतन का 6.5%

परंतु यदि कोई अधिकारी किराए की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भत्ता, जिस वेतनमान में वह है उसके प्रथम प्रक्रम के 1.75% से अधिक, उसके द्वारा अपने आवास के लिए दिया गया वास्तविक किराया ऊपर स्तंभ (2) में उल्लिखित पूर्वोक्त दरों के अनुसार देय मकान किराया भत्ते का अधिकतम 150% देय होगा ।

टिप्पणी:- अपने स्वामित्व आवास की लागत से जुड़े हुए मकान किराए भत्ते हेतु अधिकारियों के दावे अब मकान किराए भत्ते के 150% तक ही सीमित होंगे।”

7. उक्त विनियमों के विनियम 23 में,

- (i) उप-विनियम (1) में, आंकड़ों, पत्रों और शब्दों के लिए “01 नवंबर 2002” को “01 नवंबर 2007” के आंकड़ों, पत्रों और शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) उप-विनियम (2) में, आंकड़ों, पत्रों और शब्दों के लिए “01 नवंबर 2002” को “01 नवंबर 2007” के आंकड़ों, पत्रों और शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) उप-विनियम (3), (4) और (5) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे :-

“(3) 01 नवंबर 2007 को और उसके बाद से, यदि कोई अधिकारी ग्रुप ए या ग्रुप बी की किसी परियोजना क्षेत्र में सेवारत है तो, वह निर्धारित ग्रुप ए या ग्रुप बी में क्रमशः ₹290 प्रतिमाह या ₹255 प्रतिमाह की दर से परियोजना क्षेत्र क्षतिपूरक भत्ते के लिए पात्र होगा।

(4) 01 नवंबर 2007 को और उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी का स्थानांतरण किसी शैक्षणिक वर्ष के मध्य में एक स्थान से दूसरे स्थान को किया जाता है और यदि पूर्ववर्ती स्थान पर उसके एक या अधिक बच्चे स्कूल अथवा कॉलेज के विद्यार्थी हैं तो उसे दूसरे स्थान पर कार्यग्रहण करने की तिथि से शैक्षणिक वर्ष के अंत तक सभी बच्चों के लिए ₹700/- प्रति माह का मध्य शैक्षणिक वर्ष स्थानांतरण भत्ता देय होगा, परंतु पूर्ववर्ती स्थान में सभी बच्चों द्वारा अध्ययन समाप्त करने पर उस भत्ते का भुगतान स्वतः ही समाप्त हो जाएगा।

(5) 1 मई 2010 को और उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक से बाहर सेवा के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह प्रतिनियुक्ति के पद पर देय उन सभी परिलिखियों को प्राप्त करने के लिए अपना विकल्प दे सकता है, विकल्पतः वह अपने वेतन के अतिरिक्त वेतन का 7.75% अधिकतम ₹2300/- प्रतिमाह प्रतिनियुक्ति भत्ता और ऐसे अन्य भत्ते ले सकता है जो उसे उसी स्थान पर बैंक की सेवा में तैनात होने की स्थिति में मिलते।

परंतु, यदि उसे उसकी प्रतिनियुक्ति से पूर्व उसकी तैनाती के स्थान पर ही स्थित किसी संगठन में प्रतिनियुक्त किया जाता है तो उसे उसके वेतन का 4% अधिकतम ₹1200/- प्रतिमाह प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा।

परंतु यह भी कि जिस अधिकारी को बैंक के प्रशिक्षण संस्थान में संकाय सदस्य के रूप में, प्रतिनियुक्त किया जाता है, उसे उसके वेतन का 4% अधिकतम ₹1200/- प्रतिमाह प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा।”

- (iv) उप-विनियम (8) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(8) 01 नवंबर 2007 को और उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी का एक दिन का कार्य-समय दो घंटों के न्यूनतम अंतराल के साथ विभाजित होता है तो वह ₹165/- प्रति माह की दर से विभाजित छूटी भत्ते के लिए पात्र होगा।”

(v) उप-विनियम (10) में,

- (क) आंकड़ों, पत्रों और शब्दों के लिए, “01 नवंबर 2002” को “01 नवंबर 2007” के आंकड़ों, पत्रों और शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ख) तालिका के लिए, निम्नलिखित तालिका को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

तालिका

स्थान	दर
(1)	(2)
(i) 1000 मीटर और उससे अधिक किंतु 1500 मीटर से कम ऊँचाई वाले स्थान और मरकारा टाउन	वेतन का 2% अधिकतम ₹550/- प्रतिमाह
(ii) 1500 मीटर और उससे अधिक परंतु 3000 मीटर से कम ऊँचाई वाले स्थान	वेतन का 2½% अधिकतम ₹680/- प्रतिमाह
(iii) 3000 मीटर और उससे अधिक ऊँचाई वाले स्थान	वेतन का 5% अधिकतम ₹1570/- प्रतिमाह

8. उक्त विनियमों के विनियम 24 में, खंड (क) के लिए उप-विनियम (1) में, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(क) चिकित्सा सहायता - 01 नवंबर 2007 को और उसके बाद से निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित श्रेणी में कार्यरत प्रत्येक अधिकारी अपने एवं अपने परिवार के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए निम्नलिखित तालिका में निर्दिष्ट राशि का पात्र होगा। यह प्रतिपूर्ति अधिकारी द्वारा दिए गए स्वयं के प्रमाण-पत्र में उल्लेखित व्यय विवरण के अनुरूप की जाएगी, अर्थात् :-

तालिका

श्रेणी	प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा
कनिष्ठ प्रबंधन और मध्य प्रबंधन श्रेणी	₹5100/- या वास्तविक व्यय, इनमें जो भी कम हो
वरिष्ठ प्रबंधन और उच्च कार्यपालक श्रेणी	₹6320/- या वास्तविक व्यय, इनमें जो भी कम हो

टिप्पणी:- (i) अधिकारी को अप्रयुक्त चिकित्सा सहायता संचित करने की अनुमति दी जा सकती है जो किसी भी समय दी जाने वाली उपर्युक्त अधिकतम राशि की तीन गुने से अधिक न हो, या

(ii) वर्ष 2007 के लिए, चिकित्सा सहायता के अधीन चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति दो महीनों अर्थात् नवंबर 2007 और दिसंबर 2007 के लिए आनुपातिक रूप से बढ़ाई जाएगी।

स्पष्टीकरण - इस विनियम के उद्देश्य के लिए,

- (i) जिन स्थितियों में अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक हो उन सभी मामलों में अधिकारी के लिए 100% और उसके परिवार के सदस्यों के लिए 75% तक चिकित्सालयवास के व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी, या
- (ii) 01 मई 2010 को या उसके बाद से, इस विनियम के अंतर्गत किसी अधिकारी के चिकित्सालयवास व्ययों की प्रतिपूर्ति कामगार कर्मचारियों के लिए द्विपक्षीय समझौता दिनांक 27 अप्रैल, 2010 के अंतर्गत दिए गए चिकित्सालयवास योजना के नियम एवं शर्तों के अनुसार होगा, बशर्ते वे नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित सीमा के अधीन हो, अर्थात् :-

तालिका

(क) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान I और मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II एवं III	<ul style="list-style-type: none"> (i) बिस्तर शुल्क स्वयं - ₹700/- प्रति दिन परिवार - ₹525/- प्रति दिन (ii) अन्य प्रभार कामगार कर्मचारियों को लागू चिकित्सालयवास योजना के अंतर्गत दी गई सीमा का 125% के मान पर
(ख) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान IV एवं V और उच्च कार्यपालक श्रेणी वेतनमान VI एवं VII	<ul style="list-style-type: none"> (i) बिस्तर शुल्क स्वयं - ₹900/- प्रति दिन परिवार - ₹675/- प्रति दिन (ii) अन्य प्रभार कामगार कर्मचारियों को लागू चिकित्सालयवास योजना के अंतर्गत दी गई सीमा का 150% के मान पर।”

9. उक्त विनियमों के विनियम 25 में, उप-विनियम (2) के लिए, निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(2) उप-विनियमन (1) में किसी बात के बावजूद, यदि बैंक चाहे तो वह अधिकारी को आवास उपलब्ध करा सकता है जिसके लिए अधिकारी 01 नवंबर 2007 को और उसके बाद से, अपने वेतनमान के प्रथम प्रक्रम के 1.20% के बराबर राशि या आवास के लिए मानक किराये का, इनमें जो भी कम हो, भुगतान करेगा :

परंतु जहाँ ऐसे आवास पर फर्नीचर उपलब्ध कराया जाता है, वहाँ बैंक द्वारा अधिकारी से उसके वेतनमान, जिसमें वह रखा गया है, के प्रथम प्रक्रम के 0.25% के बराबर अतिरिक्त राशि वसूल की जाएगी :

परंतु यह भी कि जहाँ बैंक द्वारा ऐसी आवास व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है वहाँ बिजली, पानी, गैस और सफाई प्रभार अधिकारी द्वारा वहन किए जाएंगे।”

10. उक्त विनियमों के विनियम 36 में, उप-विनियम (2) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम को जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

“(3) 01 मई 2010 से प्रभावी होने पर, 12 महीनों की समग्र अवधि के भीतर, अधिकतम 45 दिनों तक गर्भाशयोच्चेदन के मामले में छुट्टी भी दी जा सकती है।”

11. उक्त विनियमों के विनियम 41 में, खंड (क) के लिए उप-विनियम (4) में, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(क) विराम भत्ता – 01 मई 2010 को और उसके बाद से, नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (1) में निर्धारित श्रेणी या वेतनमान में एक अधिकारी, प्रतिदिन स्तंभ (2) में निर्धारित की गई दरों पर ‘विराम भत्ता’ पाने का हकदार होगा, अर्थात् :-

तालिका

अधिकारियों की श्रेणी/ वेतनमान	प्रमुख 'ए' वर्ग के नगर	झेत्र-1	अन्य स्थान
(1)	(2)		
	₹	₹	₹
वेतनमान IV और उससे ऊपर के अधिकारी	1000	800	700
वेतनमान I/ II/ III के अधिकारी	800	700	600

परंतु, वेतनमान IV और उनसे ऊपर के अधिकारियों के मामले में, चार महानगरों यानि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई में बाहरी कार्य के दौरान प्रतिदिन ₹1200/- और वेतनमान I या II या III के अधिकारियों के लिए प्रतिदिन ₹1000/- की दर से विराम भत्ता देय होगा :

परंतु यह भी कि, यदि अनुपस्थिति की कुल अवधि 8 घंटे से कम, किंतु 4 घंटे से अधिक है तो, ऊपर बताई गई दरों की आधी दर से विराम भत्ता देय होगा ।

स्पष्टीकरण – विराम भत्ता की संगणना के लिए ‘प्रतिदिन’ का अभिप्राय है 24 घंटे की अवधि या उसके बाद का कोई भी भाग, जिसकी गणना विमान यात्रा के मामले में रिपोर्ट करने के समय तथा अन्य मामलों में प्रस्थान के लिए नियत समय से लेकर पहुंचने के वास्तविक समय तक की जाएगी । यदि अनुपस्थिति की कुल अवधि 24 घंटे से कम है तो ‘प्रतिदिन’ का अभिप्राय होगा, ऐसी अवधि जो 8 घंटे से कम नहीं है।’

12. उक्त विनियमों के विनियम 42 में, उप-विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियमों को जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

“(4) 01 मई 2010 को या उसके बाद से, स्थानांतरण पर जाने वाला कोई अधिकारी पैकिंग, स्थानीय परिवहन, यात्री सामान का बीमा आदि से जुड़े व्यय के लिए नीचे दी गई तालिका के अनुसार एकमुश्त राशि आहरित करने के लिए पात्र होगा, अर्थात् :-

तालिका

श्रेणी	एकमुश्त राशि
उच्च कार्यपालक और वरिष्ठ प्रबंधन	₹12000
मध्य प्रबंधन और कनिष्ठ प्रबंधन	₹9000”

13. उक्त विनियमों के विनियम 44 में, उप-विनियम (3) में, निम्नलिखित प्रावधान शामिल किए जाएंगे, अर्थात् :-

“परंतु, 01 मई 2010 से प्रभावी, कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान I में एक अधिकारी, जो छुट्टी यात्रा रियायती का लाभ उठा रहा है, सबसे कम किराया अर्थव्यवस्था वर्ग में हवाई यात्रा करने का हकदार होगा, उस स्थिति में वास्तविक किराया या यात्रा की दूरी के लिए ट्रेन द्वारा ऐसी प्रथम श्रेणी के लिए लागू किराया, जो भी कम है, की प्रतिपूर्ति की जाएगी और समान नियम मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II व III के अधिकारी के लिए भी लागू होंगे, जो छुट्टी यात्रा रियायती का लाभ उठा रहा है, जहाँ यात्रा की दूरी 1000 किमी. से कम है।”

14. उक्त विनियमों के विनियम 45 में,

(i) उप-विनियम (1) में, निम्नलिखित प्रावधान शामिल किए जाएंगे, अर्थात् :-

“परंतु यह कि 01 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद बैंकों की सेवाओं में शामिल होने वाले अधिकारियों के लिए कोई प्रोविडेंट फंड नहीं होगा।”

(ii) उप-विनियम (3) में, खंड (ख) के बाद और टिप्पणी के पहले, निम्नलिखित खंड को शामिल किया जाएगा, अर्थात् :-

“(ग) अंशदायी भविष्य निधि योजना के तहत कवर किए गए अधिकारियों, जो पेंशन योजना के लिए विकल्प नहीं देते हैं, अंशदायी भविष्य निधि योजना के तहत जारी रहेंगे।”

(iii) उप-विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम को शामिल किया जाएगा, अर्थात् :-

“(4) 01 अप्रैल 2010 को या उसके बाद बैंक की सेवाओं में शामिल होने वाले अधिकारियों को एक निश्चित अंशदायी पेंशन योजना के तहत कवर किया जाएगा, जहाँ अधिकारी 10% वेतन और महंगाई भत्ते का योगदान देगा तथा बैंक, भारत सरकार की अधिसूचना फा.सं.5/7/2003-ईसीबी एवं पीआर दिनांक 22 दिसंबर, 2003 जैसा कि समय-समय पर संशोधित है, के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नई पेंशन योजना (एनपीएस) में, अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधानों के अनुसार समान राशि का योगदान देगा।

15. उक्त विनियमों की अनुसूची के लिए, निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“कार्पोरेशन बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम 1979 की अनुसूची

(विनियम 23 का उप-विनियम (ii) देखें)

01 नवंबर, 2007 से एक अधिकारी, विशेष क्षेत्रीय भत्ता जो उसे वापस लेने तक या पूर्ण या पाक्षिक रूप से संशोधन करने के समय तक, के लिए पात्र होगा जो तालिका में निम्नवत् दर्शाया गया है, जैसे :-

तालिका

क्रम संख्या	ऐसा स्थान जहाँ भत्ता देय होगा	देय भत्ते की दर	
		‘14,700 से कम वेतन के लिए	‘14,700 से अधिक वेतन के लिए
1	2	3	4
1.	<p>मिजोरम</p> <p>(क) मिजोरम का चिंपतुईपुई जिला और मिजोरम के लुंगलाई जिले के लुंगलाई शहर से 25 किलोमीटर के बाद के क्षेत्र</p>	2000	2600
	<p>(क) मिजोरम के लुंगलाई शहर से 25 किलोमीटर के बाद के क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण लुंगलाई जिला</p> <p>(ग) मिजोरम का संपूर्ण आईजोल जिला</p>	1600 1200	2100 1500
2.	नागालैंड	1600	2100
3.	<p>अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह</p> <p>(क) उत्तर एवं मध्य अंडमान, छोटा अंडमान, निकोबार एवं नारकोंडम द्वीप समूह</p> <p>(ख) दक्षिण अंडमान (पोर्ट ब्लेयर सहित)</p>	2000 1600	2600 2100
4.	सिक्किम	2000	2600

5.	लक्ष्मीप द्वीप समूह	2000	2600
6.	असम	320	400
7.	मेघालय	320	400
8.	त्रिपुरा (क) त्रिपुरा के दुष्कर क्षेत्र (ख) दुष्कर क्षेत्रों को छोड़कर सारा त्रिपुरा	1600 2000	2100 1500
9.	मणिपुर	1200	1500
10.	अरुणाचल प्रदेश (क) अरुणाचल प्रदेश के दुष्कर क्षेत्र (ख) दुष्कर क्षेत्रों को छोड़कर सारा अरुणाचल प्रदेश	2000 1600	2600 2100
11.	जम्मू और कश्मीर (क) कुरुआ जिला : नियाबत बानी, लोही, मलहार और मछोड़ी	2000	2600
	(ख) उधमपुर जिला : (i) दुड़ु बसंतगढ़, लांडर भामाग इलाका, इनके अलावा जो भाग 2(ख) में सम्मिलित थे। (ii) मोहरे तहसील के कंबन पक्ष से गोयल तक के क्षेत्र तथा कियासी पक्ष से अर्नासी तक के क्षेत्र।	2000 1600	2600 2100
	(ग) डोडा जिला : किश्तवार तहसील के नियाबत नोगाम तथा पद्दर के इलाके (घ) लेह जिला : जिले के सभी स्थान (ङ) वारामुला जिला : (i) संपूर्ण गुरेज-निराबत, तंगदर उप-मंडल तथा केरन इलाका (ii) मांचिल (च) पूँछ तथा रजौरी जिला : पूँछ तथा रजौरी शहर और सुंदरबनी एवं दोनों जिलों के अन्य शहरी क्षेत्रों को छोड़कर पूँछ तथा रजौरी जिले के क्षेत्र (छ) उपर्युक्त (क) से (च) में शामिल नहीं किए गए क्षेत्र किंतु वास्तविक नियंत्रण रेखा से 8 कि.मी की दूरी में आने वाले ऐसे स्थान जहाँ सीमा भत्ते के लिए राज्य सरकार द्वारा उनके कर्मचारियों को समय-समय पर पात्र घोषित किया गया है।	2000 2000 2000 1600 1200 1200	2600 2600 2600 2100 1500 1500
12.	हिमाचल प्रदेश (क) चंवा जिला (i) पंगी तहसील, भारमौर तहसील, पंचायत: बडगांव, बजोल, दओल कुगटी, नया गांम तथा दुंडा, गाँव: जगत ग्राम पंचायत का घाटु, चौहाता ग्राम पंचायत का कनारसी (ii) भरमौर तहसील, उपर्युक्त मद (i) में शामिल गावों एवं पंचायतों को छोड़कर	2000 1600	2600 2100

	(iii) भटियाट तहसील का झंडु पंचायत, चुराह तहसील, डलहौजी टाउन (बनिष्ठेत सहित)	1200	1500
	(ख) किन्नौर जिला :		
	(i) आश्रंग, चिट्कुल तथा हांगो कुनो/चरंग पंचायत, 15/20 क्षेत्र जिसमें छोटा खंबा, नथपा तथा रुपी के ग्राम पंचायत हैं, पूह सब-डिविजन, उक्त विनिर्दिष्ट पंचायत क्षेत्र को छोड़कर।	2000	2600
	(ii) उपर्युक्त (क) में शामिल क्षेत्र के अलावा संपूर्ण जिले	1600	2100
	(ग) कुल्लू जिला :		
	(i) निर्मांद तहसील के 15/20 क्षेत्र जिसमें खर्गा, कुशवार तथा सर्गा ग्राम पंचायत शामिल हैं।	2000	2600
	(ii) आउटर-सेराज (निर्मांद तहसील के बरौ तथा जकत-खाना के गावों को छोड़कर) तथा संपूर्ण जिला (पंड्रिविस के परगना तथा आउटर सेराज क्षेत्र को छोड़कर किंतु निर्मांद तहसील के बरौ एवं जगत-खाना गांव को शामिल कर)	1200	1500
	(घ) लाहौल तथा स्पिति जिला :	2000	2600
	लाहौल तथा स्पिति के संपूर्ण क्षेत्र		
	(ङ) शिमला जिला :		
	(i) रामपुर तहसील के 15/20 क्षेत्र जिसमें कूट, लवाना-सदाना, सरपारा तथा चडी-ब्रांदा के पंचायत शामिल हैं।	2000	2600
	(ii) दोरा-कावर तहसील, रामपुर का दरकली ग्राम पंचायत, काशापथ तहसील तथा मुनिश, परगना सराहान का घोरी चाइविस।	1600	2100
	(iii) चोपल तहसील तथा घोरिस, पंजगांव, पाटस्तौ, नौविस तथा सरहन परगना का तीन कोटी, तकलेश क्षेत्र का द्योती ग्राम पंचायत, परगना बराविस, रामपुर कस्वा तथा रामपुर तहसील के परगना रामपुर का घोरी नोग, शिमला शहर तथा उसके उपनगर (धाली, जटोग, कसुमपत्ती, मशोब्रा, तारादेवी एवं दुटु)	1200	1500
	(च) कांगड़ा जिला :		
	(i) बड़ा भंगल तथा छोटा भंगल के क्षेत्र	1600	2100
	(ii) कांगड़ा जिले का धर्मशाला शहर तथा धर्मशाला शहर में शामिल किंतु नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित निम्नलिखित कार्यालय - महिला आईटीआई, दारी, मेकनिकल वर्कशोप, रामनगर, बाल कल्याण तथा शहर एवं देश आयोजना कार्यालय, सकोह, लोवर सकोह का सीआरएसएफ कार्यालय, कांगड़ा दुग्ध आपूर्ति योजना, दुग्धियार, एचआरटीसी वर्कशोप, सधेर, मंडल मलेरिया कार्यालय, दारी, वन निगम कार्यालय, शामनगर, चाय फैक्टरी, दारी, आईपीएच सब-डिविजन, दान, निपटान कार्यालय, शामनगर, हिनवा परियोजना, शामनगर।	1200	1500
	कांगड़ा जिले के पालमपुर टाउन, पालमपुर में एचपीकेवीवी कैपस और नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित निम्नलिखित कार्यालय, किंतु पालमपुर टाउन में शामिल- एच.पी. कृषि विश्वविद्यालय परिसर, पशु विकास कार्यालय/जर्सी फार्म, बनूरी, रेशम उत्पादन कार्यालय/ इंडो-जर्मन कृषि वर्कशोप/ एचपीपीडब्ल्यूडी डिवीजन, बुन्दला, इलेक्ट्रिकल सब-डिवीजन, लोहाना, डी.पी.ओ. निगम, बुन्दला, इलेक्ट्रिकल एचईएसईई डिवीजन, घुगर।		

	(छ) मंडी जिला : जोगिंदर नगर तहसील का छुहर घाटी, थुनाग के पंचायत बागड़ा, छत्री, छोटधार, गरगुशैन, गटू, गर्यास, जंजेली, जर्यार, जोहर, कलहनी, कल्वान, खोलनाल, लोथ, सिलिबागी, सोमचान, थछधार, ताची, थाना, धरमपुर ब्लॉक के पंचायत— बिंगा, कामला, सकलाना, तन्यार तथा ताराखोला, कसोग तहसील के पंचायत— बलिधार, बागड़ा, गोपालपुर, खजोल, महोग, मेहदी, मंज, पेखी, सैंज, साराहन और तेबान, सुंदरनगर तहसील के पंचायत— बोही, बटवारा, धन्यारा, पौड़ा-कोठी, सेरी, शोजा ।	1200	1500
	(ज) सिरमौर जिला : बनी, बखाली (पाछ्ड तहसील), भडोग, भेनेडी (पौंटा तहसील), बिडला (नाहन तहसील), डिब्ड (पाछ्ड तहसील) और थाना कसोगा (नाहन तहसील) के पंचायत ।	1200	1500
	(i) सोलन जिला : मंगल पंचायत (झ) हिमाचल प्रदेश के शेष क्षेत्र जो उपर्युक्त मद (क) से (i) में शामिल नहीं हैं ।	1200 320	1500 400
13.	उत्तराखण्ड चमौली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग और चंपावती जिले के क्षेत्र ।	2000	2600"

विवरणात्मक ज्ञापन

ऐसे विनियमों जिनको पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया है, वे विशिष्ट जनादेश के आधार पर सदस्य बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ के बीच, संबंधित बैंकों और बैंकों के शीर्ष स्तर के अधिकारी संघ द्वारा दिए गए संयुक्त नोट पर हस्ताक्षरित नियमों एवं शर्तों के अनुसार हैं। इसलिए, इस तरह के पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पी. वी. हेमचंद्र राव,
सहायक महा प्रबंधक

नोट : मूल विनियम भारत के राजपत्र में दिनांक 30.09.2000 को प्रकाशित किए गए और बाद में निम्न दिनांकों को प्रकाशित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए:

1. 01.02.2006
2. 23.09.2006
3. 15.01.2011
4. 01.11.2014

सं. का.प्र.प्र.औ.सं:2470:2017-18- बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 की उपधारा (2) के खंड (एफ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्पोरेशन बैंक का निदेशक मंडल भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके और केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से, कार्पोरेशन बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम 1995 में संशोधन कर एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात - :

1. (1) ये विनियम कार्पोरेशन बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम 2017 कहलाएंगे ।
- (2) इन विनियमों में अन्यथा स्पष्टतया उपलब्ध को छोड़कर, ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. कार्पोरेशन बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 में (इसके बाद कहे गये विनियमों के रूप में संदर्भित), - विनियम 2, के खंड (एस) में उपखंड (सी) के बाद निम्नांकित उप खंड जोड़ा जाए, अर्थातः-

(टी) मई 2005 के प्रथम दिवस या उसके बाद सेवा में रहते हुए सेवानिवृत्त या मृत्यु होने पर किसी कर्मचारी के संबंध में, बैंक में अपनी सेवा के पिछले दस महीनों के दौरान कर्मचारी द्वारा आहरित, नियत वेतन वृद्धि सहित मूल वेतन, यदि कोई हो, और विशेष वेतन, स्नातक वेतन, व्यावसायिक योग्यता वेतन, नियत कार्मिक वेतन का वेतन वृद्धि घटक और स्थानापन्न वेतन, यदि कोई हो,;

परंतु 01 मई 2005 से प्रभावी इस खंड के प्रावधानों में अप्रैल 1998 के प्रथम दिवस पर या उसके बाद लेकिन 30 अप्रैल 2005 से पहले सेवा में सेवानिवृत्त या मृत्यु हो जाने वाले किसी कर्मचारी के संबंध में प्रभाव पड़ेगा।

3. उक्त विनियमों के विनियम 3 के उप – विनियम (4) में, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

"(4) (क) अधिसूचित तिथि के बाद और 31 मार्च 2010 को या उससे पहले बैंक की सेवा में सेवारत होः"

(ख) उप – विनियम 10 के बाद, निम्नलिखित उप-विनियमों को सम्मिलित किया जायेगा, अर्थातः -

(11) जो बैंक की सेवा में 29 सितम्बर 1995 से पहले थे और 27 अप्रैल 2010 तक बैंक की सेवा में सेवारत रहे हों, वर्षते कि ऐसे कर्मचारी निपटान में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा और शर्तों का पालन करते हों;

(12) जो बैंक की सेवा में 29 सितम्बर 1995 से पहले थे तथा उस तिथि से और 27 अप्रैल 2010 से पहले सेवानिवृत्त हुए हों, वर्षते कि ऐसे कर्मचारी निपटान में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा और शर्तों का पालन करते हों;

(13) जो बैंक की सेवा में 29 सितंबर 1995 से पहले थे और उस तिथि के बाद सेवानिवृत्त हुए और मृत्यु हो गई हो, ऐसे मामलों में जैसा कि इन विनियमों के अधीन यथास्थिति, उनके परिवार को पेंशन या उनके परिवार पेंशन के हकदार होंगे, यदि मृतक का परिवार निपटान में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा और शर्तों का पालन करता हो;

(14) जो बैंक की सेवा में 29 सितंबर 1995 से पहले थे, और उस तिथि के बाद बैंक की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गई हो, ऐसे मामलों में जैसा कि इन विनियमों के अधीन यथास्थिति, उनके परिवार को पेंशन या उनके परिवार, पेंशन के हकदार होंगे, यदि मृतक का परिवार निपटान में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा और शर्तों का पालन करता हो;

4. उक्त विनियमों के विनियमन 28 में, प्रावधानों के बाद, निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित किए जाएंगे, अर्थातः -

"परंतु यह भी कि कर्मचारी जो सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण 29 सितम्बर 1995 को या उसके बाद सेवा में नहीं थे, लेकिन 15 वर्ष की न्यूनतम सेवा के उपरांत इस संबंध में बोर्ड द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार एवं सरकार द्वारा अनुमोदित, योजना में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन पेंशन फंड में शामिल होने के हकदार होंगे।"

5. उक्त विनियमों के विनियमन 36 में, -

(क) खंड (सी) में निम्नलिखित प्रावधान शामिल किए जाएंगे, अर्थातः -

"परंतु 1 मई 2005 को, या से, अंशकालिक कर्मचारी के अलावा किसी कर्मचारी के संबंध में जो 1 अप्रैल 1998 को, या उसके पश्चात, परंतु 31 अक्टूबर 2002 से पहले सेवानिवृत्त हुए, उनकी न्यूनतम पेंशन एक हजार साठ रुपये प्रतिमाह और अंशकालिक कर्मचारी के संबंध में जो 1 अप्रैल 1998 को, या उसके बाद, सेवानिवृत्त हुए एक तिहाई वेतनमान पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी की पाँच सौ तीस रुपये प्रतिमाह तथा तीन चौथाई वेतनमान पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी की सात सौ पंचानवे रुपये प्रतिमाह होगी।

(ख) खंड (सी) के बाद निम्नलिखित खंड (टी) शामिल किया जायेगा, अर्थातः -

(टी) अंशकालिक कर्मचारी के अलावा किसी कर्मचारी के संबंध में जो 1 मई 2005 को, या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए उनको एक हजार चार सौ पैंतीस रुपये प्रतिमाह और अंशकालिक कर्मचारी के संबंध में जो 1 मई 2005 को, या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए एक तिहाई वेतनमान पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी की चार सौ अस्सी रुपये प्रतिमाह, आधा वेतनमान पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी की सात सौ बीस रुपये प्रतिमाह तथा तीन चौथाई वेतनमान पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी की एक हजार अस्सी रुपये प्रतिमाह होगी।

परंतु 1 मई 2005 के प्रथम दिवस से, इस खंड के प्रावधान अंशकालिक कर्मचारी सहित किसी भी कर्मचारी पर लागू होंगे, जो 1 नवम्बर 2002 को या उसके बाद लेकिन 30 अप्रैल 2005 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए।

(ई) अंशकालिक कर्मचारी के अलावा किसी कर्मचारी के संबंध में जो नवम्बर 2007 माह के प्रथम दिवस को, या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए उनको एक हजार सात सौ उन्न्यासी रुपये प्रतिमाह और अंशकालिक कर्मचारी के संबंध में जो नवम्बर 2007 माह के प्रथम दिवस को, या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए एक तिहाई वेतनमान पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी की आठ सौ बानक्वे रुपये प्रतिमाह, आधा वेतनमान पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी की एक हजार तीन सौ उन्तालिस रुपये प्रतिमाह होगी।

(6) उक्त विनियमों के विनियम 40 के उप-विनियम (4) में,-

(i) खंड (ए) में, उप-खंड (III) के बाद, निम्नलिखित प्रावधान एवं खंड शामिल किए जाएंगे, अर्थात्:-
 'परंतु यह कि मई 2005 के प्रथम दिवस पर और से, विनियमों के इस उप-खंड में प्रभावी जैसेकि शब्दों "छह हजार सात सौ छप्पन" को शब्द "सात हजार और चालिस" से प्रतिस्थापित किया गया है।

(iv) 1 मई 2005 को या उसके बाद सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारियों के संबंध में केवल नौ हजार पाँच सौ पैसठ रुपए प्रति माह, दोनों अधिकारियों और कामगारों के लिये;

(v) 1 नवम्बर 2007 को या उसके बाद सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारियों के संबंध में केवल ग्यारह हजार आठ सौ छप्पन रुपए प्रति माह, दोनों अधिकारियों और कामगारों के लिये;

(ii) खंड (बी) में, उप-खंड (iii) के बाद, निम्नलिखित प्रावधान एवं खंड शामिल किए जाएंगे, अर्थात्:-
 'परंतु यह कि मई 2005 के प्रथम दिवस पर और से, विनियमों के इस उप-खंड में प्रभावी जैसेकि शब्दों "छह हजार सात सौ छप्पन" को शब्द "सात हजार और चालिस" से प्रतिस्थापित किया गया है।

(iv) 1 मई 2005 को या उसके बाद सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारियों के संबंध में केवल नौ हजार पाँच सौ पैसठ रुपए प्रति माह, दोनों अधिकारियों और कामगारों के लिये;

(v) 1 नवम्बर 2007 को या उसके बाद सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारियों के संबंध में केवल ग्यारह हजार आठ सौ छप्पन रुपए प्रति माह, दोनों अधिकारियों और कामगारों के लिये;

(iii) खंड (सी) में, उप-खंड (iii) के बाद, निम्नलिखित प्रावधान एवं खंड शामिल किए जाएंगे, अर्थात्:-
 'परंतु यह कि मई 2005 के प्रथम दिवस पर और से, विनियमों के इस उप-खंड में प्रभावी जैसेकि शब्दों "तीन हजार तीन सौ अठत्तर" को शब्द "तीन हजार पाँच सौ बीस" से प्रतिस्थापित किया गया है।

(iv) 1 मई 2005 को या उसके बाद सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारियों के संबंध में केवल चार हजार सात सौ तिरासी रुपए प्रति माह, दोनों अधिकारियों और कामगारों के लिये;

(v) 1 नवम्बर 2007 को या उसके बाद सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारियों के संबंध में केवल पाँच हजार नौ सौ अठाइस रुपए प्रति माह, दोनों अधिकारियों और कामगारों के लिये;

(7) उक्त विनियमों के विनियम 48 में, निम्नलिखित विनियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"48. बैंकों को हुई आर्थिक हानि की वसूली.-

(1) यदि पेंशनभोगी अपनी सेवा की अवधि के दौरान किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में घोर कदाचार या लापरवाही या आपराधिक न्यासभंग या जालसाजी या कपटपूर्ण कार्य का दोषी पाया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी पेंशन या उसका अंश रोक सकता है या आहरित कर सकता है, चाहे स्थायी रूप से या निर्धारित अवधि के लिये, और बैंक को हुई किसी भी आर्थिक हानि के पूरे या अंश को पेंशन से वसूल करने के आदेश दे सकता है।

परंतु कोई भी अंतिम आदेश जारी करने के पूर्व बोर्ड से परामर्श किया जायेगा।

परंतु जहां पेंशन के एक अंश रोक दिया गया है या आहरित किया गया है, पेंशनभोगी द्वारा आहरित पेंशन की रकम इन विनियमों के तहत देय न्यूनतम पेंशन से कम नहीं होगी।

परंतु यह भी कि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के पश्चात, विभागीय कार्यवाही, यदि कर्मचारी की सेवा में रहते हुए आरंभ की गई है, इन विनियमों के अधीन कार्यवाही समन्वी जायेगी तथा प्राधिकारी द्वारा वह आरंभ की गई थी वह उसी प्रकार से जारी रखी जायेगी तथा समाप्त की जायेगी मानो कर्मचारी सेवा में है।

(2) यदि कर्मचारी के सेवा में रहते हुए विभागीय कार्यवाही आरंभ नहीं की गई थी, तो ऐसे संस्थापन के चार वर्ष पूर्व हुई किसी भी घटना के मामले में कोई विभागीय कार्यवाही आरंभ नहीं की जायेगी।

परंतु इस प्रकार आरंभ की गई अनुशासनिक कार्यवाही, कर्मचारी की सेवा अवधि के दौरान अनुशासनिक कार्यवाही के लिये लागू प्रक्रिया के अनुसार होगी।

(3) जहाँ सक्षम प्राधिकारी पेंशन से आर्थिक हानि की वसूली का आदेश देता है वहाँ वसूली सामान्यता कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख को स्वीकार्य पेंशन के एक तिहाई से अधिक की दर पर नहीं की जायेगी।

8. उक्त विनियमों के विनियम 52 में:-

(ए) उप-विनियमन (1) के लिये, निम्नलिखित उपविनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः :-

“(1) किसी कर्मचारी के संबंध में जहाँ विनियम 34 या विनियम 46 के प्रावधान लागू होते हैं, परिवार की पेंशन के अलावा एक पेंशन उस तारीख से देय होगी, जिस पर कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है।”

(बी) उप-विनियम (3) में निम्न प्रावधान को शामिल किया जायेगा :-

“परंतु 27 अप्रैल 2010 को या उसके बाद बैंक कर्मचारी पेंशन योजना में शामिल होने वाले को परिवार पेंशन सहित पेंशन 27 नवंबर 2009 से लागू होगी।”

9. उक्त विनियम के परिशिष्ट ॥ में, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः :-

परिशिष्ट ॥

(विनियम 37 देखें)

मूल पेंशन पर महंगाई राहत निम्नलिखित अनुसार होगी :-

(1) अधीनस्थ श्रेणी के जो कर्मचारी, 01 जनवरी 1986 को या उसके पश्चात, परंतु 01 नवंबर 1992 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे, तथा अधिकारी श्रेणी के जो कर्मचारी 01 जनवरी 1986 को या उसके पश्चात परंतु 01 जुलाई 1993 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे, के मामले में, महंगाई भत्ता शुंखला $1960=100$ में औद्योगिक कामगारों के लिये अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 600 अंकों के ऊपर, यथास्थिति 4 अंकों की वृद्धि पर देय होगा तथा प्रत्येक गिरावट पर वसूली योग्य होगा। ऐसे प्रत्येक 4 अंकों की महंगाई राहत में वृद्धि या गिरावट नीचे दिये गये अनुसार परिकलित की जायेगी :

मूल पेंशन का वेतनमान

प्रतिमाह

(1)

(i) रु. 1250/- तक

(ii) रु. 1251/- से रु. 2000/-

(iii) रु. 2001/- to रु. 2130/-

(iv) रु 2130/- से अधिक

मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में

महंगाई राहत की दर

(2)

0.67 प्रतिशत

रु. 1250/- का 0.67 प्रतिशत तथा + रु. 1250/- से अधिक मूल वेतन का 0.55 प्रतिशत

रु. 1250/- का 0.67 प्रतिशत तथा + रु. 2000/- और रु. 1250/- के बीच के अंतर का 0.55 प्रतिशत तथा रु. 2000/- से अधिक मूल पेंशन का 0.33 प्रतिशत।

रु 1250/- का 0.67 प्रतिशत तथा + रु 2000/- और रु. 1250/- के बीच के अंतर का 0.55 प्रतिशत तथा + रु. 2130/- और रु. 2000/- के बीच के अंतर का 0.33 प्रतिशत तथा + रु. 2130/- से अधिक मूल पेंशन का 0.17 प्रतिशत।

(2) कामगार श्रेणी के जो कर्मचारी 01 नवंबर 1992 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए हैं तथा अधिकारी श्रेणी के जो कर्मचारी 01 जुलाई 1993 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए हैं, के मामले में, महंगाई भत्ता शुरूखला 1960=100 में औद्योगिक कामगारों के लिये अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 1148 अंकों के ऊपर, यथास्थिति, प्रत्येक 4 अंकों की वृद्धि पर देय होगा तथा प्रत्येक गिरावट पर वसूली योग्य होगा । ऐसे प्रत्येक 4 अंकों की महंगाई राहत में वृद्धि या गिरावट नीचे दिये गये अनुसार परिकलित की जायेगी :

मूल पेंशन का वेतनमान प्रतिमाह	मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में महंगाई राहत की दर
(1)	(2)
(i) रु. 2400/- तक	0.35 प्रतिशत
(ii) रु. 2401/- से रु.3850/-	रु. 2400/- का 0.35 प्रतिशत तथा + रु. 2400/- से अधिक मूल पेंशन का 0.29 प्रतिशत ।
(iii) रु. 3851/- से रु.4100/-	रु. 2400/- का 0.35 प्रतिशत तथा + रु.3850/- और रु. 2400/- के बीच के अंतर का 0.29 प्रतिशत तथा + रु. 3850 से अधिक मूल पेंशन का 0.17 प्रतिशत ।
(iv) रु.4100/- से अधिक	रु. 2400/- का 0.35 प्रतिशत तथा + रु. 3850/- और रु. 2400/- के बीच के अंतर का 0.29 प्रतिशत तथा + रु. 4100/- और रु. 3850/- के बीच के अंतर का 0.17 प्रतिशत तथा + रु. 4100/- से अधिक मूल पेंशन का 0.09 प्रतिशत ।

(3) जो कर्मचारी 1 अप्रैल 1998 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें महंगाई राहत शुरूखला 1960=100 में औद्योगिक कामगारों के लिये अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 1616 से अधिक प्रत्येक 4 अंकों की, यथास्थिति, प्रत्येक वृद्धि के लिये देय होगी तथा प्रत्येक गिरावट के लिये वसूली योग्य होगी । ऐसे प्रत्येक 4 अंकों की महंगाई राहत में वृद्धि या गिरावट नीचे दिये गये अनुसार परिकलित की जायेगी :-

मूल पेंशन का वेतनमान प्रतिमाह	मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में महंगाई राहत की दर
(1)	(2)
(i) रु. 3380/- तक	0.25 प्रतिशत
(ii) रु. 3381/- से रु.5420/-	रु. 3380/- का 0.25 प्रतिशत तथा + रु. 3380/- से अधिक मूल पेंशन का 0.21 प्रतिशत ।
(iii) रु. 5421/- से रु.5770/-	रु. 3380/- का 0.35 प्रतिशत तथा + रु.5420/- और रु. 3380/- के बीच के अंतर का 0.21 प्रतिशत + रु. 5420 से अधिक मूल पेंशन का 0.12 प्रतिशत ।
(iv) रु.5770/- से अधिक	रु. 3380/- का 0.25 प्रतिशत तथा + रु. 5420/- और रु. 3380/- के बीच के अंतर का 0.21 प्रतिशत तथा + रु. 5770/- और रु. 5420/- के बीच के अंतर का 0.12 प्रतिशत तथा + रु. 5770/- से अधिक मूल पेंशन का 0.06 प्रतिशत ।

परंतु, 1 मई 2005 पर या से कर्मचारियों के संबंध में जो 1 अप्रैल 1998 को या उसके पश्चात लेकिन 31 अक्टूबर 2002 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें महंगाई राहत शुरूखला 1960=100 में औद्योगिक कामगारों के लिये अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 1684 से अधिक प्रत्येक 4 अंकों की, यथास्थिति, प्रत्येक वृद्धि के लिये देय होगी तथा प्रत्येक गिरावट के लिये वसूली योग्य होगी । ऐसे प्रत्येक 4 अंकों की महंगाई राहत में वृद्धि या गिरावट नीचे दिये गये अनुसार परिकलित की जायेगी ::-

मूल पेंशन का वेतनमान प्रतिमाह	मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में महंगाई राहत की दर
(1)	(2)
(i) रु. 3550/- तक	0.24 प्रतिशत
(ii) रु. 3551/- से रु. 5660/-	रु. 3550/- का 0.24 प्रतिशत तथा + रु. 3550/- से अधिक मूल पेंशन का 0.20 प्रतिशत ।
(iii) रु. 5651/- से रु. 6010/-	रु. 3550/- का 0.24 प्रतिशत तथा + रु. 5650/- और रु. 3550/- के बीच के अंतर का 0.20 प्रतिशत + रु. 5650/- से अधिक मूल पेंशन का 0.12 प्रतिशत ।
(iv) रु. 6010/- से अधिक	रु. 3550/- का 0.24 प्रतिशत तथा + रु. 5650/- और रु. 3550/- के बीच के अंतर का 0.20 प्रतिशत तथा + रु. 6010/- और रु. 5650/- के बीच के अंतर का 0.12 प्रतिशत तथा + रु. 6010/- से अधिक मूल पेंशन का 0.06 प्रतिशत ।

4) 1 मई 2005 पर या उसके पश्चात सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में, महंगाई राहत शृंखला 1960=100 में अद्यौगिक कामगारों के लिये अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 2288 से अधिक प्रत्येक 4 अंकों की, यथास्थिति, प्रत्येक वृद्धि के लिये देय होगी तथा प्रत्येक गिरावट के लिये वसूली योग्य होगी । उपभोक्ता प्रत्येक 4 अंकों के लिये महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या गिरावट मूल पेंशन की 0.18 प्रतिशत की दर से परिकलित की जायेगी:-

परंतु 1 मई 2005 पर या से, कर्मचारियों के संबंध में जो 01 नवम्बर 2002 को या उसके बाद लेकिन 30 अप्रैल 2005 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए हैं, महंगाई राहत इस खंड की शर्तों के अनुसार देय होगी :

परंतु 1 नवंबर 2007 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में, महंगाई राहत शृंखला 1960=100 में अद्यौगिक कामगारों के लिये अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 2836 से अधिक प्रत्येक 4 अंकों की, यथास्थिति, प्रत्येक वृद्धि के लिये देय होगी तथा प्रत्येक गिरावट के लिये वसूली योग्य होगी । उपभोक्ता प्रत्येक 4 अंकों के लिये महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या गिरावट मूल पेंशन की 0.15 प्रतिशत की दर से परिकलित की जायेगी:-

- (5) महंगाई भत्ता पिछले वर्ष के अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर के महीनों में प्रकाशित सूचकांकों के तिमाही औसत पर पहली फरवरी से आरंभ और 31 जुलाई को समाप्त होने वाली छमाही के लिये और उसी वर्ष अप्रैल, मई और जून के महीनों में प्रकाशित सूचकांकों के तिमाही औसत पर और 01 अगस्त से आरंभ और 31 जनवरी को समाप्त होने वाली छमाही के लिये देय होगा ।
- (6) परिवार पेंशन, अशक्तता पेंशन और अनुकम्पा भत्ते के संबंध में महंगाई राहत ऊपर उल्लिखित दरों के अनुसार देय होगी ।
- (7) पूर्ण मूल पेंशन पर महंगाई राशि की अनुमति संराशीकरण के बाद भी दी जायेगी ।
- (8) महंगाई राहत अतिरिक्त पेंशन पर देय नहीं हैं ।
- (9) जिस पेंशनभोगी की मूल पेंशन न्यूनतम पेंशन से कम है परंतु मूल पेंशन तथा अतिरिक्त पेंशन का योग न्यूनतम पेंशन से अधिक है, वह न्यूनतम पेंशन पर लागू महंगाई राहत आहृत कर सकेगा ।

10. उपरोक्त विनियमों में परिशिष्ट ॥। के लिये निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

“परिशिष्ट ॥।

(विनियम 39 देखें)

परिवार पेंशन की साधारण दरें इस प्रकार होंगी :-

- (क) कर्मचारियों के मामले में, अंशकालिक कर्मचारियों को छोड़कर, जहाँ कर्मचारी कामगार श्रेणी में था और 01 नवम्बर 1992 के पूर्व सेवानिवृत्त हुआ था या जहाँ कर्मचारी अधिकारी वर्ग में था और 01 जुलाई 1993 के पूर्व सेवानिवृत्त हुआ था:-

वेतनमान प्रतिमाह

(1)

मासिक परिवार पेंशन की राशि

(2)

रु. 1500/- तक

'वेतन' का 30 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 30 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 375/- प्रतिमाह से कम नहीं होगा।

रु. 1501 से रु. 3000

'वेतन' का 20 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 20 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 450/- प्रतिमाह से कम नहीं होगा।

रु.3000 से अधिक

'वेतन' का 15 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 15 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 600/- प्रतिमाह से कम तथा रु. 1250/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा।

(ख) कर्मचारियों के मामले में, अंशकालिक कर्मचारियों को छोड़कर, जहाँ कर्मचारी कामगार श्रेणी में था और 01 नवम्बर 1992 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुआ था या जहाँ कर्मचारी अधिकारी वर्ग में था और 01 जुलाई 1993 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुआ था :-

वेतनमान प्रतिमाह

(1)

मासिक परिवार पेंशन की राशि

(2)

रु.2870 तक

'वेतन' का 30 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 30 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 720/- प्रतिमाह से कम नहीं होगा।

रु.2871 से रु.5740

'वेतन' का 20 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 20 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 860/- प्रतिमाह से कम नहीं होगा।

रु.5740 से अधिक

'वेतन' का 15 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 15 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 1150/- प्रतिमाह से कम तथा रु. 2400/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा।

(ग) 01 अप्रैल 1998 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले अंशकालिक कर्मचारियों को छोड़कर कर्मचारियों (अधिकारी तथा कामगार दोनों) के मामले में :-

वेतनमान प्रतिमाह

(1)

मासिक परिवार पेंशन की राशि

(2)

रु.4040 तक

'वेतन' का 30 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 30 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 1015/- प्रतिमाह से कम नहीं होगा।

रु.4041 से रु.8080

'वेतन' का 20 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 20 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 1212/- प्रतिमाह से कम नहीं होगा।

रु.8080 से अधिक

'वेतन' का 15 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 15 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 1616/- प्रतिमाह से कम तथा रु. 3378/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा।

परंतु, 01 मई 2005 से, अंशकालिक कर्मचारियों को छोड़कर, कर्मचारियों (अधिकारी तथा कामगार दोनों) के मामले में जो 01 अप्रैल 1998 को या उसके पश्चात परंतु 31 अक्टूबर 2002 को या उससे पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे, परिवार पेंशन की साधारण दरें इस प्रकार होंगी :-

वेतनमान प्रतिमाह

(1)

मासिक परिवार पेंशन की राशि

(2)

रु.4210 तक

'वेतन' का 30 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 30 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 1056/- न्यूनतम प्रतिमाह होगा।

रु.4211 से रु.8420

'वेतन' का 20 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 20 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 1262/- न्यूनतम प्रतिमाह होगा।

रु.8420 से अधिक

'वेतन' का 15 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 15 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 1687/- न्यूनतम प्रतिमाह तथा अधिकतम रु. 3521/- प्रतिमाह होगा।

(घ) 01 मई 2005 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले अंशकालिक कर्मचारियों को छोड़कर कर्मचारियों (अधिकारी तथा कामगार दोनों) के संबंध में:-

वेतनमान प्रतिमाह

(1)

मासिक परिवार पेंशन की राशि

(2)

रु.5720 तक	'वेतन' का 30 प्रतिशन मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 30 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 1435/- न्यूनतम प्रतिमाह होगा।
रु.5721 से रु.11440	'वेतन' का 20 प्रतिशन मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 20 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 1715/- न्यूनतम प्रतिमाह होगा।
रु.11440 अधिक	'वेतन' का 15 प्रतिशन मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 15 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 2292/- न्यूनतम प्रतिमाह तथा अधिकतम रु. 4784/- प्रतिमाह होगा।

परंतु, 01 मई 2005 से, अंशकालिक कर्मचारियों को छोड़कर, कर्मचारियों (अधिकारी तथा कामगार दोनों) के मामले में जो 01 नवम्बर 2002 को या उसके पश्चात परंतु 30 अप्रैल 2005 को या उससे पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे, परिवार पेंशन की साधारण दरें इस खंड के अनुसार निम्न होंगी :-

(च) 01 मई 2007 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले अंशकालिक कर्मचारियों को छोड़कर कर्मचारियों (अधिकारी तथा कामगार दोनों) के संबंध में:-

वेतनमान प्रतिमाह

(1)

मासिक परिवार पेंशन की राशि

(2)

रु.7090 तक	'वेतन' का 30 प्रतिशन मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 30 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 1779/- न्यूनतम प्रतिमाह होगा।
रु.7091 से रु.14180	'वेतन' का 20 प्रतिशन मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 20 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 2186/- न्यूनतम प्रतिमाह होगा।
रु.14180 से अधिक	'वेतन' का 15 प्रतिशन मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 15 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 2841/- न्यूनतम प्रतिमाह तथा अधिकतम रु. 5930/- प्रतिमाह होगा।

टिप्पणी :-

- (1) महंगाई भत्ता अतिरिक्त परिवार पेंशन पर देय नहीं होगा।
- (2) उपर्युक्त अनुसार परिवार पेंशन की गणना के प्रयोजन से वेतनमान, विनियम 2 के उप खंड (एस) में निर्धारित 'वेतन' तथा विनियम 35 के उप-विनियम (3) की व्याख्या में निर्धारित भत्तों का योग होगा।
- (3) अंशकालिक कर्मचारी के मामले में, परिवार पेंशन की न्यूनतम तथा अधिकतम राशि, कर्मचारी द्वारा आहरित वेतन की दर के अनुपात में होगी।
- (4) यदि मूल परिवार पेंशन तथा अतिरिक्त पेंशन का कुल योग न्यूनतम पेंशन से कम होता है तो पेंशनभोगी को न्यूनतम पेंशन दी जाए और ऐसी न्यूनतम परिवार पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान किया जाए। लेकिन, न्यूनतम परिवार पेंशन के अतिरिक्त परिवार पेंशन नहीं दी जाएगी।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

पूर्वव्यापी प्रभाव से दिए गए उक्त विनियमों को संयुक्त नोटों और निपटान के लिये सहमत नियमों व शर्तों के अनुसार, संबंधित बैंकों द्वारा दिए गए विशेष अधिदेश के आधार पर सदस्य बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ और बैंकों के शीर्ष स्तर के कामगार संघों तथा अधिकारी संघों के बीच हस्ताक्षरित है। इसलिए, इस तरह के पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पी. वी. हेमचंद्र राव,

सहायक महा प्रबंधक

नोट : मूल विनियम 29.09.1995 में प्रकाशित किए गए और बाद में भारत के राजपत्र के भाग III, खण्ड 4 में निम्न दिनांकों को प्रकाशित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए-

1. 27.02.1999
2. 01.03.2003
3. 05.06.2004
4. 11.09.2004
5. 11.09.2010
6. 01.11.2014

CORPORATION BANK

(A Premier Public Sector Bank)

(Head Office, Mangalore)

Mangalore, the 17th February, 2018

No. PAD:IR:2469:2017-18.—In exercise of the powers conferred by Section 19, read with sub-section (2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), the Board of Directors of the Corporation Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Corporation Bank (Officers') Service Regulations, 1982, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Corporation Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2017.
(2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of November, 2007, except as otherwise provided in these regulations.
2. In the Corporation Bank (Officers') Service Regulations, 1982 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 3,-
 - (i) for clause (g), the following clause shall be substituted, namely:-

“(g) “family” means the spouse of the officer, wholly dependent unmarried children (including step children and legally adopted children), physically challenged brother or sister with forty per cent, or more disability and parents ordinarily residing with and wholly dependent on the officer’.

Explanation - For the purposes of this clause a child or parent or physically challenged brother or sister shall be deemed to be dependent on the officer if the monthly income of such child, parent, brother or sister does not exceed Rs.3,500 per month.

Provided that if the income of one of the parents exceeds Rs.3,500 per month or the aggregate income of both the parents exceeds Rs.3,500 per month, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the officer.’
 - (ii) Clause (o) shall be omitted.
3. In regulation 4 of the said regulations,-
 - (i) sub-regulation (4A) shall be omitted;
 - (ii) after sub-regulation (4A) as so omitted, the following sub-regulations shall be inserted, namely:-

“(5) With effect from the 1st November, 2007, the scales of pay specified against each grade shall be as under :

 - (a) Top Executive Grade
Scale VII = Rs.46800 – 1300/4 – 52000
Scale VI = Rs.42000 - 1200/4 – 46800
 - (b) Senior Management Grade
Scale V = Rs.36200 – 1000/2 – 38200 – 1100/2 - 40400
Scale IV = Rs.30600 – 900/4 – 34200– 1000/2 – 36200
 - (c) Middle Management Grade
Scale III = Rs.25700 - 800/5— 29700 - 900/2 - 31500
Scale II = Rs.19400 - 700/1 - 20100 -800/10 - 28100
 - (d) Junior Management Grade
Scale I = Rs.14500-600/7- 18700-700/2- 20100- 800/7-25700.

Explanation.— Every officer who is governed by the scales of pay in force as on the 31st October, 2007 shall be fitted in the scale of pay set out in this sub-regulation as on 1st November, 2007 on stage to stage basis, i.e. on corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual except where provided otherwise.

(6) Nothing in sub-regulations (1), (2), (3), (4) and (5) shall be construed as requiring the Bank to have at all times, officers serving in all these grades.”.

4. In regulation 5 of the said regulations, -

(a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation, shall be substituted, namely: -

“(1) Subject to the provisions of sub-regulation (5) of regulation 4, on and from the 1st November, 2007, the increments shall be granted subject to the following, namely: -

(a) the increments specified in the scales of pay set out in sub-regulation (5) of regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due;

(b) officers in Junior Management Grade Scale I who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale II after reaching maximum of the higher scale shall be eligible for four stagnation increments for every three completed years of service of which first two shall be Rs.800 each and next two Rs.900 each:

Provided that officers who have completed three years or more after receipt of the second stagnation increment as on 1st November, 2007 shall get the third stagnation increment on 1st November, 2007 and another stagnation increment on or after the 1st November, 2008 on their completion of six years after receipt of second stagnation increment;

(c) officers in Middle Management Grade Scale II who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale III after reaching maximum of higher scale shall be eligible for three stagnation increments of Rs.900 each for every three completed years of service:

Provided that officers who have completed three years or more after receipt of the first stagnation increment as on the 1st November, 2007 shall get the next stagnation increment with effect from the 1st November, 2007 and a subsequent stagnation increment on or after the 1st November, 2008 on their completion of six years after receipt of the first stagnation increment:

Provided further the officers appointed to or promoted in substantive Middle Management Grade Scale III, shall be eligible for four stagnation increments of Rs.900 each for every three completed years of service or :

Provided also that the officers who have already received two stagnation increments and completed more than three years of service after receipt of second stagnation increment as on the 1st November, 2007 shall get the third stagnation increment on the 1st November, 2007 and the fourth stagnation increment, on or after the 1st November, 2008 on completion of six years after receipt of second stagnation increment.

Explanation.— Grant of such increments in the next higher scale under this sub-regulation shall not amount to promotion and the privileges, perquisites, duties and responsibilities of the officers shall continue as of their substantive posts.

(b) in sub-regulation (2),-

(i) in the Explanation, after clause (e) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:-

“(f) on and from the 1st day of November, 2007, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as under:-

TABLE

Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.410 per month one year after reaching maximum of the Scale.
Those who have passed both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.410 per month after one year on reaching maximum of the Scale. (ii) Rs.1030 per month after two years on reaching maximum of the Scale;

Provided that an Officer acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers (either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay, shall be granted from the date of acquiring such qualification the first installment of Professional Qualification Pay and the release of subsequent installments of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of first installment of Professional Qualification Pay:

Provided further that in a case where an officer, has already acquired any of the above qualifications and has not earned any increment or Professional Qualification Pay on account of acquiring such qualification, he may be granted the Professional Qualification Pay, with effect from the 1st November 2007 or the date of acquiring such qualification/s, whichever is later.”;

(ii) in the Note, for clause (v), the following clause shall be substituted, namely:-

“(v) if an officer, as on the 27th April 2010 has already acquired any of the said qualifications referred to in clause (iv) and has not earned any increment or Professional Qualification Pay on account of acquiring such qualification, he shall be granted the Professional Qualification Pay, with effect from the 1st day of November, 2007 or the date of acquiring such qualification, whichever is later.”;

(c) in sub-regulation (3)-

(i) after clause (d) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:-

“(e) on and from the 1st November, 2007, other things being equal, Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance shall be at the following rates and shall remain frozen for the entire period of service:-

TABLE

Increment Component (Rs.)	Dearness Allowance as on 01.11.2007 on the increment components (Rs.)	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided (Rs.)
(A)	(B)	(C)
800	58	858
900	65	965
1000	72	1072
1100	79	1179
1200	86	1286
1300	94	1394”,

(ii) in the Note, for clauses (i) and (ii), the following clauses shall be substituted, namely:-

“(i) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as indicated under column (C) of the Table under clauses (b), (c), (d) or (e) shall be payable to those officers who are provided with bank's accommodation.

(ii) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be the aggregate amount specified under columns (A) and (B) of the Table under clause (e) and House Rent Allowance drawn by the concerned officer employees when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub-regulations (2), (3), (4) or (5) of regulation 4 is earned.”;

(iii) clause (e) occurring after the Note shall be renumbered as sub-clause (v) thereof and for clause (v) as so numbered, the following clause be substituted, namely:-

“(v) An officer who has earned the advance increment as in clause (a) above shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay as mentioned in clauses (b), (c), (d) or (e) above, one year after reaching the maximum of the scale”;

5. In regulation 21 of the said regulations, -

(i) in sub-regulation (3), the Note shall be omitted;

(ii) in sub-regulation (4), the Note shall be omitted;

(iii) after sub-regulation (4), the following sub-regulation and Note shall be inserted, namely:-

“(5) On and from the 1st day of November, 2007, dearness allowance shall be payable for every rise or fall of four points over 2836 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100 at 0.15% of Pay.

Explanation.- For the purposes of this sub-regulation,-

(a) “pay” for the purpose of Dearness Allowance shall mean basic pay including Stagnation Increments;

(b) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as specified in Explanations (c), (d), (e) and (f) to sub-regulation (2) of regulation 5 shall rank for dearness allowance’.

6. In regulation 22 of the said regulations, for sub-regulations(1) and (2), the following sub-regulations shall be substituted, namely:-

“(1) on and from the 1st day of November, 2002,

(a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 1.75 per cent of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;

(b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following table, namely:

TABLE

Where the place of work is in	HRA payable shall be
(1)	(2)
(i) Major “A” Class Cities and Project Area Centres in Group A	8.5% of Pay
(ii) Other places in Area I and Project Area Centres in Group B	7.5% of Pay
(iii) Other places	6.5% of Pay:

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 1.75 per cent of pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent of the House Rent Allowance payable as per column (2) of the above Table.

(2) on and from the 1st day of November, 2007, -

(a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 1.20 per

cent of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;

(b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following table, namely: -

TABLE

Where the place of work is in	HRA payable shall be
(1)	(2)
(i) Major "A" Class Cities and Project Area Centres in Group A	8.5% of Pay
(ii) Other places in Area I and Project Area Centres in Group B	7.5% of Pay
(iii) Other places	6.5% of Pay

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 1.20 per cent of Pay in the first stage of the Scale of Pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent of the House Rent Allowance payable as per aforesaid rates mentioned in column (2) above.

Note.- The claims of officers for House Rent Allowance linked to the cost of their ownership accommodation shall also be restricted to 150 per cent of House Rent Allowance as hitherto.”;

7. In regulation 23 of the said regulations,-

- (i) in sub-regulation (1), for the figures, letters and words “1st day of November 2002”, the figures, letters and words “1st day of November 2007” shall be substituted;
- (ii) in sub-regulation (2), for the figures, letters and words “1st day of November 2002, the figures, letters and words “1st day of November 2007” shall be substituted;
- (iii) for sub-regulations (3), (4) and (5), the following sub-regulations shall be substituted, namely:-
 - (3) On and from the 1st day of November, 2007, if an officer is serving in an area to be specified as Project Area falling in Group A or Group B, he shall be eligible for a Project Area Compensatory Allowance at the rate of Rs.290 per month or Rs.255 per month according to the classification of area as Group A or Group B.
 - (4) On and from the 1st day of November, 2007, if an officer is transferred from one place to another in the midst of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance of Rs.700 per month from the date he reports to the latter place upto the end of the academic year in respect of all the children, provided that such allowance shall cease if all the children cease studying at the former place.
 - (5) On and from the 1st day of May, 2010, if an officer is deputed to serve outside the Bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75 per cent of pay subject to a maximum Rs.2300 per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the Bank’s service at that place:

Provided that where he is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he shall receive a deputation allowance equal to 4 per cent of his pay subject to a maximum Rs.1200 per month:

Provided further that an officer on deputation to the Training Establishment of the Bank as a faculty member shall be eligible for deputation allowance at the rate of 4 per cent of his pay subject to a maximum Rs.1200 per month.”;

- (iv) for sub-regulation (8), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(8) on and from the 1st day of November 2007, if the working hours during a day are split with minimum interval of two hours, an officer shall be eligible for a Split Duty Allowance at the rate of Rs.165 per month.”;

(v) in sub-regulation (10),-

(a) for the figures, letters and words “1st day of November 2002”, the figures, letters and words “1st day of November, 2007” shall be substituted;

(b) for the Table, the following Table shall be substituted, namely:-

“TABLE

Place (1)	Rate (2)
(i) Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town	2% of pay subject to a maximum of Rs.550 per month
(ii) Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres	2½% of pay subject to a maximum of Rs.680 per month
(iii) Place with an altitude of 3000 metres and above	5% of pay subject to a maximum of Rs.1570 per month”;

8. In regulation 24 of the said regulations, in sub-regulation (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

“(a) Medical Expenses.- On and from the 1st day of November 2007, an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength of the officer’s own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the table below, namely:-

TABLE

Grade	Maximum limit of reimbursement
Junior Management and Middle Management Grade	Rs.5100 or the amount incurred whichever is less
Senior Management and Top Executive Grade	Rs.6320 or the amount incurred whichever is less

Note.- (i) an officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above or;

(ii) for the year 2007, the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for two months, that is, November 2007 and December, 2007.

Explanation. - for the purposes of this regulation,-

(i) hospitalisation charges shall be reimbursed to the extent of 100 per cent in the case of an officer and 75 per cent, in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalization or;

(ii) on and from the 1st day of May, 2010, reimbursement of hospitalisation expenses under this regulation shall be in accordance with the terms and conditions of Hospitalisation Scheme as laid down under the Bipartite Settlement dated the 27th day of April, 2010 for workmen employees, subject to the limits as specified in the table below, namely:-

TABLE

(a) Junior Management Grade Scale I and Middle Management Grade Scales II and III.	(i) Bed Charges Self – Rs.700 per day Family – Rs.525 per day (ii) Other charges At the scale of 125% of the limits laid down under the Hospitalisation Scheme applicable to workmen employees.
(b) Senior Management Grade Scales IV and V and Top Executive Grade Scales VI and VII.	(i) Bed Charges Self – Rs.900 per day Family – Rs.675 per day (ii) Other charges At the scale of 150% of the limits laid down under the Hospitalisation Scheme applicable to workmen employees.”;

9. In regulation 25 of the said regulations, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation(1), it shall be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, on and from the 1st day of November, 2007, a sum equal to 1.20 per cent, of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.25 per cent of basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed shall be recovered by the Bank from him:

Provided further that, where such residential accommodation is provided by the bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.”.

10. In regulation 36 of the said regulations, after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely :-

“(3) With effect from the 1st day of May 2010, within the overall period of 12 months, leave may also be granted in case of hysterectomy upto a maximum of 45 days.”.

11. In regulation 41 of the said regulations, in sub-regulation (4), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

‘(a) Halting Allowance – On and from the 1st day of May, 2010, an officer in the Grades or Scales set out in column (1) of the Table below shall be entitled to ‘per diem’ Halting Allowance at the corresponding rates set out in column (2) thereof, namely:-

TABLE

Grades/Scales of officers	Major ‘A’ Class cities	Area I	Other Places
(1)	(2)		
	Rs.	Rs.	Rs.
Officers in Scale IV and above	1000	800	700
Officers in Scale I/II/III	800	700	600

Provided that in the case of officers in Scale IV and above, Halting Allowance payable per diem while on outstation work at the four metros, viz., Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai, shall be Rs.1200 and for officers in Scale I or II or III, the per diem Halting Allowance and shall be Rs.1000:

Provided further that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

Explanation.— For the purpose of computing Halting allowance “per diem” shall mean each period of twenty-four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty-four hours, “per diem” shall mean a period of not less than eight hours.’.

12. In regulation 42 of the said regulations, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(4) On and from the first day of May 2010, an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc., as specified in the Table below, namely:-

“TABLE

Grade	Lump Sum
Top Executive and Senior Management	Rs.12,000
Middle Management and Junior Management	Rs.9,000”.

13. In regulation 44 of the said regulations, in sub-regulation (3), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that with effect from the 1st May 2010, an officer in Junior Management Grade Scale I while availing Leave Travel Concession shall be entitled to travel by air in the lowest fare economy class in which case the reimbursement will be the actual fare or the fare applicable to AC First Class fare by train for the distance traveled, whichever is less and the same rules shall apply to an officer in Middle Management Grade Scale II and Middle Management Grade Scale III while availing Leave Travel Concession where the distance is less than 1000 kms.”.

14. In regulation 45 of the said regulations, -

(i) in sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that there shall be no Provident Fund to Officers joining the services of the Banks on or after the 1st day of April, 2010.”;

(ii) in sub-regulation (3), after clause (b) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:-

“(c) Officers who are covered under the Contributory Provident Fund Scheme who do not opt for Pension Scheme shall continue under the Contributory Provident Fund Scheme.”;

(iii) after sub-regulation(3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(4) The officers joining the services of the Bank on or after the 1st day of April 2010 shall be covered by a Defined Contributory Pension Scheme, where the officer shall contribute ten per cent, of pay plus Dearness Allowance and the Bank shall make the similar amount of contribution in accordance with the provisions of the Contributory Pension Scheme in accordance with New Pension Scheme notified by the Central Government vide notification of the Government of India, F.No.5/7/2003-ECB & PR dated the 22nd December, 2003, as amended from time to time.”

15. For the Schedule to the said regulations, the following Schedule shall be substituted, namely,:-

“Schedule to Corporation Bank (Officers’) Service Regulations, 1979

[See sub-regulation (ii) of regulation 23]

With effect from the 1st day of November, 2007, an officer shall be eligible for the Special Area Allowance till such time they are withdrawn or modified either wholly or partially, as specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs.14,700/-	Pay above Rs.14,700/-
1	2	3	4
1.	Mizoram		
	(a) Chimgtupui District of Mizoram and areas beyond 25 kms. from Lunglei Town in Lunglei District of Mizoram.	2000	2600
	(b) Throughout Lunglei District excluding areas beyond 25 kms. from Lunglei town of Mizoram.	1600	2100
	(c) Throughout Aizawl District of Mizoram	1200	1500
2.	Nagaland	1600	2100
3.	Andaman and Nicobar Islands		
	(a) North Andaman, Middle Andamans, Little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands	2000	2600
	(b) South Andaman (including Port Blair)	1600	2100
4.	Sikkim	2000	2600
5.	Lakshadweep Islands	2000	2600
6.	Assam	320	400
7.	Meghalaya	320	400
8.	Tripura		
	(a) Difficult areas of Tripura	1600	2100
	(b) Throughout Tripura except difficult areas.	1200	1500
9.	Manipur	1200	1500
10.	Arunachal Pradesh		
	(a) Difficult areas of Arunachal Pradesh	2000	2600
	(b) Throughout Arunachal Pradesh other than difficult areas.	1600	2100

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs.14,700/-	Pay above Rs.14,700/-
1	2	3	4
11.	Jammu and Kashmir (a) Kathua District: Niabat Bani, Lohi, Malhar and Machhodi	2000	2600
	(b) Udhampur District: (i) Dudu Basantgarh, Lander Bhamag Illaqa, other than those included in Part 2(b). (ii) Areas upto Goel from Kamban Side and areas upto Arnas from Keasi side in Tehsil Mohre.	2000 1600	2600 2100
	(c) Doda District: Illaquas of Padder and Niabat Nowgam in Kishtwar Tehsil (d) Leh District : All places in the District (e) Barmulla District (i) Entire Gurez-Nirabat, Tangdar Sub-Division and Keran Illaqua (ii) Matchill (f) Poonch and Rajouri District : Areas in Poonch and Rajouri District excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two Districts. (g) Areas not included in items (a) to (f) above, but which are within the distance of 8 kms. from the line of Actual Control or at places which may be declared as qualifying for border allowance from time-to-time by the State Government for their own staff.	2000 2000 2000 1600 1200 1200	2600 2600 2600 2100 1500 1500
12.	Himachal Pradesh (a) Chamba District (i) Pangi Tehsil, Bharmour Tehsil, Panchayats : Badgaun, Bajol, Deol Kugti, Nayagam and Tundah, Villages: Ghatu of Gram Panchayat Jagat, Kanarsi of Gram Panchayat Chauhata (ii) Bharmour Tehsil, excluding Panchayats and Villages included in item (i) above. (iii) Jhandru Panchayat in Bhatiyat Tehsil, Churah Tehsil, Dalhousie Town (including Banikhet proper).	2000 1600 1200	2600 2100 1500
	(b) Kinnaur District: (i) Asrang, Chitkul and Hango Kuno/ Charang Panchayats, 15/ 20 Area comprising the Gram Panchayats of Chhota Khamba, Nathpa and Rupi, Pooh Sub-Division, excluding the Panchayat Areas specified above. (ii) Entire District other than Areas included in (a) above. (c) Kullu District: (i) 15/20 Area of Nirmand Tehsil, comprising the Gram Panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga	2000 1600 2000	2600 2100 2600

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs.14,700/-	Pay above Rs.14,700/-
1	2	3	4
	(ii) Outer-Saraj (excluding villages of Jakat-Khana and Burrow in Nirmand Tehsil) and entire District excluding outer Seraj area and pargana of Pandrabis but including villages Jagat-Khana and Burrow of Tehsil Nirmand).	1200	1500
	(d) Lahaul and Spiti District : Entire area of Lahaul and Spiti	2000	2600
	(e) Shimla District : (i) 15/20 area of Rampur Tehsil comprising of Panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chadi-Branda.	2000	2600
	(ii) Dora-Kawar Tehsil, Gram Panchayat of Darkali in Rampur, Kashapath Tehsil and Munish, Ghori Chaibis of Pargana Sarahan.	1600	2100
	(iii) Chopal Tehsil and Ghoris, Panjgaon, Patsnau, Naubis and Teen Koti of Pargana Sarahan, Deothi Gram Panchayat of Taklesh Area, Pargana Barabis, Kasba Rampur and Ghori Nog of Pargana Rampur of Rampur Tehsil, Simla Town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu).	1200	1500
	(f) Kangra District: (i) Areas of Bara Bhangal and Chhota Bhangal	1600	2100
	(ii) Dharamshala Town of Kangra District and the following offices located outside the Municipal limits but included in Dharamshala Town—Women's ITI, Dari, Mechanical Workshop, Ramnagar, Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh, CRSF Office at lower Sakoh, Kangra Milk Supply Scheme, Dugiar, HRTC Workshop, Sadher, Zonal Malaria Office, Dari, Forest Corporation Office, Shamnagar, Tea Factory, Dari, I.P.H. Sub-Division, Dan, Settlement Office, Shamnagar, Hinwa Project, Shamnagar. Palampur Town of Kangra District including HPKVV Campus at Palampur and the following offices located outside its municipal limits but included in Palampur Town – H.P. Krishi Vishwavidyalaya Campus, Cattle Development Office/Jersey Farm, Banuri, Sericulture Office/Indo-German Agriculture Workshop/HPPWD Division, Bundla, Electrical Sub-Division, Lohna, D.P.O. Corporation, Bundla, Electrical HESEE Division, Ghuggar.	{ 1200 1500 }	{ 1500 }
	(g) Mandi District: Chhuhar Valley of Jogindernagar Tehsil, Panchayats in thunag Tehsil-of Bagraa, Chatri, Chhotdhar, Garagushain, Gatoo, Garyas, Janjehli, Jaryar, Johar, Kalhani, Kalwan, Kholanal, Loth, Silibagi, Somachan, Thachdhar, Tachi, Thana, Panchayats of Dharampur Block- Binga, Kamlah, Salkana, Tanyar and Tarakholah, Panchayats of Karsog Tehsil – Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol, Mahog, Mehudi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban, Panchayats of Sundernagar Tehsil – Bohi, Batwara, Dhanyara, Paura-Kothi, Seri and	{ 1200 }	{ 1500 }

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs.14,700/-	Pay above Rs.14,700/-
1	2	3	4
	Shoja. (h) Sirmaur District: Panchayats of Bani, Bakhali (Pachhad Tehsil), BharogBheneri (Paonta Tehsil), Birla (Nahan Tehsil), Dibber (Pachhad Tehsil) and Thana Kasoga (Nahan Tehsil) and Thansgiri Tract	{ 1200	{ 1500
	(i) Solan District : Mangal Panchayat. (j) Remaining areas of Himachal Pradesh not included in items (a) to (i) above.	1200	1500 320
13.	Uttarakhand Areas under Chamoli, Pithoragarh, Uttarkashi, Rudraprayag and Champavat Districts.	2000	2600”

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Regulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the Joint Notes signed between the Indian Banks' Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level officers' associations of the Banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.

P. V. HEMACHANDRA RAO,
Assistant General Manager

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India on 30.09.2000 and subsequently amended vide notifications published on:

1. 01.02.2006
2. 23.09.2006
3. 15.01.2011
4. 01.11.2014

No. PAD:IR:2470:2017-18.—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (2) of section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Corporation Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the (Corporation Bank (Employees') Pension Regulations, 1995, namely :-

1. (1) These regulations may be called the Corporation Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2016.
- (2) Save as otherwise expressly provided in these regulations, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Corporation Bank (Employees') Pension Regulations 1995 (hereinafter referred to as the said regulations), -

In regulation 2, in clause (s), after sub-clause(c), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

“(d) in relation to an employee who retired or died while in service on or after the first day of May, 2005 the basic pay including stagnation increments, if any, and Special pay, Graduation Pay, Professional Qualification Pay, increment component of Fixed Personnel Pay and Officiating Pay, if any, drawn by the employee during the last ten months of his service in the Bank:

Provided that with effect from 1st day of May, 2005 the provisions of this clause shall have effect in relation to an employee who retired or died while in service on or after 1st day of April, 1998 but before 30th day of April, 2005.”.

3. In regulation 3 of the said regulations, for sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(4) (a) join the service of the bank on or after the notified date and on or before the 31st day of March, 2010;”.

(b) after sub-regulation (10), the following sub-regulations shall be inserted, namely:-

“(11) were in the service of the Bank prior to the 29th September, 1995 and continue in the service of the Bank as on the 27th April, 2010 provided such employee meets the requirement and comply with the conditions laid down in the settlement;

(12) were in the service of the Bank prior to the 29th September, 1995 and retired after that date and prior to 27th April, 2010 provided such employee meets the requirements and comply with the conditions laid down in the settlement;

(13) were in service of the Bank, prior to the 29th September, 1995 retired after that date and had died in which case their family shall be entitled to the pension or the family pension, as the case may be under these regulations, if the family of the deceased meets the requirement and complies with the conditions laid down in the settlement;

(14) were in the service of the bank prior to the 29th September, 1995 and died while in service of the Bank after that date in which case their family shall be entitled to the pension or the family pension, as the case may be under these regulations, if the family of the deceased meet the requirement and complies with the conditions laid down in the settlement.”.

4. In regulation 28 of the said regulations, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided further that employees who ceased to be in service on or after the 29th September, 1995 on account of voluntary retirement before attaining the age of superannuation but after rendering service for a minimum period of 15 years in accordance with the Scheme framed in this regard by the Board with the approval of the Government, shall be entitled to join the Pension Fund, subject to the compliance of the terms and conditions mentioned in the Scheme.”.

5. In regulation 36 of the said regulations,-

(a) in clause (c), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that on and from the 1st day of May, 2005 the amount of minimum pension, in respect of an employee, other than a part-time employee, who retired on or after the 1st April, 1998 but before the 31st October, 2002 shall be rupees one thousand and sixty per month and rupees three hundred and fifty five in respect of a part-time employee drawing 1/3 scale wages, rupees five hundred and thirty in respect of a part-time employee drawing 1/2 scale wages and rupees seven hundred and ninety five in respect of a part-time employee drawing 3/4 scale wages, where the part-time employee retired on or after 1st day of April, 1998.”;

(b) after clause (c), the following clause (d) shall be inserted namely:-

“(d) rupees one thousand four hundred and thirty five per month in respect of an employee, other than a part-time employee, where the employee retired on or after 1st day of May 2005 and rupees four hundred and eighty per month in respect of a part-time employee drawing 1/3 scale of wages, rupees seven hundred and twenty per month in respect of part-time employee drawing ½ scale wages and rupees one thousand and eighty per month in respect of a part-time employee drawing ¾ scale wages, where the part-time employee retired on or after the 1st day of May 2005:

Provided that on and from the 1st day of May 2005 the provisions of this clause shall also apply to an employee including a part-time employee who retired on or after 1st November 2002 but on or before 30th April 2005.;

(e) rupees one thousand seven hundred and seventy nine per month in respect of an employee, other than a part-time employee, where the employee retired on or after 1st day of November 2007 and rupees five hundred and ninety five per month in respect of a part-time employee drawing 1/3 scale of wages, rupees eight hundred and ninety two per month in respect of part-time employee drawing ½ scale of wages and rupees one thousand three hundred and thirty nine per month in respect of a part-time employee drawing ¾ scale wages, where the part-time employee retired on or after the 1st day of November 2007.”.

(6) In regulation 40, of the said regulations, in sub-regulation (4),-

(i) in clause (a), after sub-clause (iii), the following proviso and clause shall be inserted, namely:-

‘Provided that on and from the 1st day of May 2005 the provisions of this sub-clause shall have effect as if for the words “six thousand seven hundred and fifty six”, the words “seven thousand and forty”, had been substituted.;

(iv) nine thousand five hundred and sixty five rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after 1st day of May 2005. ’;

(v) Eleven thousand eight hundred and fifty six rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after 1st day of November 2007.”

(ii) in clause (b), after sub-clause (iii), the following proviso and clause shall be inserted, namely:-

‘Provided that on and from the 1st day of May 2005 the provisions of this sub-clause shall have effect as if for the words “six thousand seven hundred and fifty six”, the words “seven thousand and forty”, had been substituted;

(iv) nine thousand five hundred and sixty five rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after 1st day of May 2005. ’;

(v) Eleven thousand eight hundred and fifty six rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after 1st day of November 2007.

(iii) in clause (c), after sub-clause (iii), the following proviso and clause shall be inserted, namely:-

‘Provided that on and from the 1st day of May 2005 the provisions of this sub-clause shall have effect as if for the words “three thousand three hundred and seventy eight,” the words “three thousand five hundred and twenty,” had been substituted.;

(iv) four thousand seven hundred and eighty three rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after 1st day of May 2005. ’.

(v) five thousand nine hundred and twenty eight rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after 1st day of November 2007.

(7) For regulation 48 of the said regulations, the following regulations shall be substituted, namely:-

“48. Recovery of pecuniary loss caused to Bank.

(1) The Competent Authority may withhold or withdraw a pension or a part thereof, whether permanently or for a specified period, and order recovery from pension of the whole or part of any pecuniary loss caused to the Bank if in any departmental or judicial proceedings the pensioner is found guilty of grave misconduct or negligence or criminal breach of trust or forgery or for acts

done fraudulently during the period of his service:

Provided that the Board shall be consulted before any final orders are passed:

Provided further that where a part of pension is withheld or withdrawn the amount of pension drawn by a pensioner shall not be less than the minimum pension payable under these regulations:

Provided also that the departmental proceedings, if instituted while the employee was in service, shall, after the retirement of the employee, be deemed to be proceedings under these regulations and shall be continued and concluded by the authority by which they were commenced in the same manner as if the employee had continued in service.

(2) No departmental proceedings, if not instituted while the employee was in service, shall be instituted in respect of an event which took place more than four years before such institutions:

Provided that the disciplinary proceedings so instituted shall be in accordance with the procedure applicable to disciplinary proceedings in relation to the employee during the period of his service.

(3) Where the Competent Authority orders recovery of pecuniary loss from the pension, the recovery shall not ordinarily be made at a rate exceeding one-third of the pension admissible on the date of retirement of the employee.”.

8. In regulation 52 of the said regulations,-

(a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(1) Except in the case of an employee to whom the provisions of regulation 34 or regulation 46 apply, a pension other than family pension shall become payable from the date following the date on which an employee retires.”.

(b) in sub-regulation (3), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that pension including family pension to those who opted to join the Bank Employees’ Pension Scheme on or after the 27th April, 2010 shall be payable with effect from the 27th November, 2009.”.

9. For Appendix II to the said regulations, the following Appendix shall be substituted, namely:-

“Appendix II

(See regulation 37)

Dearness relief on basic pension shall be as under :-

(1) In the case of employees who were in the workmen cadre and who retired on or after the 1st day of January, 1986, but before the 1st day of November, 1992; and in the case of employees who were in the officers’ cadre and who retired on or after the 1st day of January, 1986, but before the 1st day of July, 1993, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 600 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960 = 100. Such increase or decrease in dearness relief for every said four points shall be calculated in the manner given below:-

Scale of basic pension per month (1)	The rate of dearness relief as a percentage of basic pension (2)
(i) Upto Rs.1250	0.67 per cent
(ii) Rs.1251 to Rs.2000	0.67 per cent of Rs.1250 plus 0.55 per cent of basic pension in excess of Rs.1250.
(iii) Rs.2001 to Rs.2130	0.67 per cent of Rs.1250 plus 0.55 per cent of the difference between Rs.2000 and Rs.1250 plus 0.33 per cent of basic pension in excess of Rs.2000.
(iv) Above Rs.2130	0.67 per cent of Rs.1250 plus 0.55 per cent the difference between Rs. 2000 and Rs.1250 plus 0.33 per cent of the difference between Rs.2130 and Rs. 2000 plus 0.17 per cent of basic pension in excess of Rs. 2130.

(2) In the case of employees who are in workmen cadre and who retire on or after the 1st day of November, 1992; and in the case of employees who are in the officers' cadre and who retire on or after the 1st day of July, 1993, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 1148 points in the quarterly average of All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960 = 100. Such increase or decrease in dearness relief for every said four points shall be calculated in the manner given below :-

Scale of basic pension per month	The rate of dearness relief as a percentage of basic pension
(1)	(2)
(i) Upto Rs.2400	0.35 per cent
(ii) Rs.2401 to Rs.3850	0.35 per cent of Rs.2400 plus 0.29 per cent of basic pension in excess of Rs.2400
(iii) Rs.3851 to Rs.4100	0.35 per cent of Rs. 2400 plus 0.29 per cent of the difference between Rs.3850 and Rs.2400 plus 0.17 per cent of basic pension in excess of Rs. 3850
(iv) above Rs.4100	0.35 per cent of Rs.2400 plus 0.29 per cent of the difference between Rs. 3850 and Rs. 2400 plus 0.17 per cent of the difference between Rs.4100 and Rs. 3850 plus 0.09 per cent of basic pension in excess of Rs. 4100
(3)	In the case of employees who retire on or after the 1 st day of April, 1998, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 1616 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said four points shall be calculated in the manner given below :-

Scale of basic pension per month	The rate of dearness relief as a percentage of basic pension
(i) Upto Rs.3380	0.25 per cent
(ii) Rs.3381 to Rs.5420	0.25 per cent of Rs.3380 plus 0.21 percent basic pension in excess of Rs.3380
(iii) Rs.5421 to Rs.5770	0.25 per cent of Rs.3380 plus 0.21 percent of the difference between Rs.5420 and Rs.3380 plus 0.12 per cent of basic pension in excess of Rs.5420.
(iv) Above Rs.5770	0.25 per cent of Rs.3380 plus 0.21 percent of the difference between Rs.5420 and Rs.3380 plus 0.12 per cent of the difference between Rs.5770 and Rs.5420 plus 0.06 per cent of basic pension in excess of Rs.5770.

Provided that on or from the 1st day of May 2005 in the case of employees who retire on or after the 1st day of April 1998 but on or before the 31st October 2002, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 1684 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated in the manner given below:

Scale of basic pension per month	The rate of dearness relief as a percentage of basic pension
(i) Upto Rs. 3550	0.24 per cent
(ii) Rs. 3551 to Rs. 5650	0.24 per cent of Rs. 3550 plus 0.20 per cent basic pension in excess of Rs. 3550
(iii) Rs. 5651 to Rs. 6010	0.24 per cent of Rs. 3550 plus 0.20 per cent of the difference between Rs. 5650 and Rs. 3550 plus 0.12 of basic pension in excess of Rs. 5650

(4) In respect of employees who retire on or after the 1st day of May, 2005, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 2288 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.18 per cent of basic pension:
Provided that on and from the 1st day of May 2005, in respect of employees who retired on or after 1st day of November 2002 but on or before 30th day of April 2005, dearness relief shall be payable in terms of this clause:
Provided further that in respect of employees who retired on or after the 1st day of November 2007, Dearness Relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 2836 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.15 per cent of basic pension.

(5) Dearness relief shall be payable for the half year commencing from the 1st day of February and ending with the 31st day of July on the quarterly average of the index figures published for the months of October, November and December of the previous year and for the half year commencing from the 1st day of August and ending with the 31st day of January on the quarterly average of the index figures published for the months of April, May and June of the same year.

(6) In the case of family pension, invalid pension and compassionate allowance, dearness relief shall be payable in accordance with the rates mentioned above.

(7) Dearness relief will be allowed on full basic pension even after commutation.

(8) Dearness relief is not payable on additional pension.

(9) Pensioner whose basic pension is less than minimum pension but the aggregate of basic pension and additional pension is more than the minimum pension shall draw dearness relief as applicable to minimum pension.”.

10. For Appendix III to the said regulations, the following Appendix shall be substituted, namely :--

“Appendix III

(See Regulation 39)

The ordinary rates of family pension shall be as under:-

(a) In respect of employees other than part-time employees, where the employee was in the workmen cadre and retired before the 1st day of November, 1992 or where the employee was in the officers' cadre and retired before the 1st day of July, 1993:-

Scale of pay per month (1)	Amount of monthly Family pension (2)
Upto Rs.1500	30 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 30 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs.375 per month.
Rs.1501 to Rs.3000	20 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 20 percent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and

additional family pension shall not be less than Rs.450 per month.

Above Rs.3000

15 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 15 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs.600 per month and not more than Rs.1250 per month.

(b) In respect of employees other than part-time employees, where the employee was in the workmen cadre and retired on or after the 1st day of November, 1992 or where the employee was in the officers' cadre and retired on or after the 1st day of July 1993:-

Scale of pay per month (1)	Amount of monthly Family Pension (2)
Upto Rs.2870	30 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 30 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.720 per month.
Rs.2871 to Rs.5740	20 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 20 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.860 per month.
Above Rs.5740	15 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 15 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.1150 per month and a maximum of Rs.2400 per month.

(c) In respect of employees (both officers and workmen) other than part-time employees retiring on or after the 1st day of April, 1998: -

Scale of pay per month (1)	Amount of monthly Family Pension (2)
Upto Rs.4040	30 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 30 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs.1015 per month.
Rs.4041 to Rs.8080	20 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 20 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs.1212 per month.

Above Rs.8080

15 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 15 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs.1616 per month and a maximum of Rs.3378 per month:

Provided that on and from the 1st day of May, 2005 in respect of the employees (both officers and workmen), other than part time employees, who retired on or after the 1st day of April 1998 but on or before the 31st day of October, 2002, the ordinary rate of family pension shall be as under:-

Scale of pay per month (1)	Amount of monthly Family Pension (2)
Up to Rs.4210	30 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 30 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.1056 p.m.
Rs.4211 to Rs.8420	20 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 20 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.1262 p.m.
Above Rs.8420	15 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 15 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.1687 p.m. and a maximum of Rs.3521 p.m.

(d) In respect of employees (both officers and workmen) other than part-time employees retiring on or after the 1st day of the May 2005:-

Scale of pay per month (1)	Amount of monthly Family Pension (2)
Upto Rs.5720	30 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 30 per cent of allowance which are counted for making contribution to Provident Fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.1435 p.m.

Rs.5721 to Rs.11440	20 per cent of the Pay shall be basic family pension plus 20 per cent of allowance which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to minimum of Rs.1715 p.m.
Above Rs.11440	15 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 15 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for the dearness allowance, shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.2292 p.m. and maximum of Rs.4784 p.m.:

Provided that on and from the 1st day of May 2005, in respect of employees who retired on or after the 1st day of November 2002 but on or before the 30th April 2005, ordinary rates of family pension shall be in terms of this clause.

(e) In respect of employees (both officers and workmen) other than part-time employees retiring on or after the 1st day of November 2007:-

Scale of pay per month (1)	Amount of monthly Family Pension (2)
Upto Rs.7090	30 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 30 per cent of allowance which are counted for making contribution to Provident Fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.1779 p.m.
Rs.7091 to Rs.14180	20 per cent of the Pay shall be basic family pension plus 20 per cent of allowance which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to minimum of Rs.2186 p.m.
Above Rs.14180	15 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 15 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for the dearness allowance, shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.2841 p.m. and maximum of Rs.5930 p.m.

Notes :-

- (1) Dearness relief is not payable on additional family pension.
- (2) Scale of pay for the purpose of calculation of family pension as above shall be the aggregate of Pay as defined in clause (s) of regulation 2 and allowances as defined in the Explanation to sub-regulation (3) of regulation 35.
- (3) In the case of a part-time employee, the minimum amount of family pension and maximum amount of family pension shall be in proportion to the rate of scale wages drawn by the employee.

(4) In case the aggregate of basic family pension and additional family pension falls short of minimum pension the pensioner may be given minimum family pension and dearness relief may be paid on such minimum family pension. However, no additional family pension shall be payable over and above the minimum family pension.”.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Regulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the settlements and Joint Notes signed between the Indian Banks' Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level workmen unions and officers' associations of the Banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.

P. V. HEMACHANDRA RAO,
Assistant General Manager

Note: The principal regulations were published on 29.09.1995 and subsequently amended vide notifications published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, on

1. 27.02.1999
2. 01.03.2003
3. 05.06.2004
4. 11.09.2004
5. 11.09.2010
6. 01.11.2014